वर्ष 13 • अंक 36 • 8 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 2 अप्रैल 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 3

2020 में सपाट रहेगा स्मार्टफोन का बाजार

हर्ष गोयनका पृष्ठ 2

15 दिन और बढ़ाई जाए लॉकडाउन की अवधि

डॉलर रु. 75.60 (बाजार बंद) | यूरो रु. 82.80 (बाजार बंद) | सोना (10ग्राम) रु. 43300 ▲ 300 रुपये | सेंसेक्स 28265.30 ▼ 1203.20 | निफ्टी 8253.80 ▼ 344.00 | निफ्टी फ्यूचर्स 8257.30 ▲ 3.50 | ब्रेंट क्रूड 20.90 डॉलर ▲ 0.60

एक नज़र

रामनवमी पर आज बंद रहेंगे शेयर और जिंस बाजार

रामनवमी पर गुरुवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिंस वायदा बाजार और मुद्रा विनिमय बाजार में अवकाश रहेगा। इसके साथ ही सराफा और प्रमुख थोक बाजार भी बंद रहेंगे।

एचयूएल ने जीएसकेसीएच का विलय पूरा किया

रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा है कि उसके साथ ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन हेल्थकेयर लिमिटेड (जीएसकेसीएच) का विलय पूरा हो गया है। एचयूएल ने एक बयान में कहा कि कंपनी को जीएसकेसीएच के विलय के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट से सभी जरूरी नियामक मंजूरियां मिल गई हैं। इसके साथ ही एचयूएल के बोर्ड ने जीएसके के लोकप्रिय ब्रांड हॉर्लिक्स को 3,045 करोड़ रुपए में अपनी मूल कंपनी यूनिलीवर में मिलाने को भी मंजूरी दी। इस विलय लिए एचयूएल अपने पास मौजूद नकदी का इस्तेमाल करेगी।

आईओसी ने तेल खरीद टालने की घोषणा की

भारत की प्रमुख तेल कंपनी आईओसी ने अपने चार प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं – सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से तेल खरीद पर अप्रत्याशित परिस्थितियों की घोषणा की है। कंपनी ने तेल की मांग कम होने से रिफाइनरियों के उत्पादन में कमी के कारण यह कदम उठाया है। सूत्रों ने कहा कि आईओसी ने चारों आपूर्तिकर्ताओं से कहा है कि अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले तेल की कुछ मात्रा को टाल दिया जाए। देशव्यापी बंदी के कारण कंपनी ने अपने उत्पादन में करीब 25 फीसदी की कटौती की है।

बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलिंडर हुआ सस्ता

बिना सब्सिडी के बाजार मूल्य आधारित रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में 61.5 रुपये की कटौती की गई है। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के अनुरूप देश में भी एलपीजी सिलिंडर सस्ते किए गए हैं। दिल्ली में अब बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिंडर का दाम 744 रुपये प्रति सिलिंडर पर आ गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की अधिसूचना के अनुसार मार्च से यह बाजार मूल्य आधारित सिलिंडर कीमत में दूसरी कटौती है। इससे पहले 1 मार्च को सिलिंडर के दाम 53 रुपये घटाए गए थे। फरवरी में बिना सब्सिडी वाले सिलिंडर के दाम में 144.5 रुपये की भारी वृद्धि की गई थी।

गोएयर ने कटौती के बाद भी किया आंशिक भुगतान

पिछले हफ्ते वेतन में कटौती की घोषणा करने के बाद गोएयर के मुख्य कार्याधिकारी विनय दुबे ने बुधवार को अपने कर्मचारियों से कहा कि मार्च में मिलने वाले वेतन का एक हिस्सा अप्रैल के लिए टाल दिया गया है। वेतन कटौती के साथ ही कंपनी ने लागत कटौती के कई उपाय किए हैं, जिनमें विदेशी पायलटों की छंटनी और बारी-बारी से कर्मचारियों को बिना वेतन के अवकाश पर जाने को कहा गया है। कई अन्य विमानन कंपनियों ने भी वेतन में कटौती की है।

एयर इंडिया के लिए बढ़ सकती है बोली की तारीख

सरकार कोविड-19 की वजह से राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया की खरीद के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख को 30 अप्रैल से आगे बढ़ा सकती है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस महामारी की वजह से वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, इस वजह से एयर इंडिया के लिए बोली की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने कर्ज के बोझ तले दबी राष्ट्रीय विमानन कंपनी में हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू की थी। बोली जमा कराने की समयसीमा को यदि बढ़ाया जाता है तो यह दूसरा मौका होगा जबकि विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने की तारीख आगे बढ़ेगी। पहले एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की अंतिम तारीख 17 मार्च थी।

आज का सवाल

कर संग्रह में कमी से सरकार की बढ़ेगी मुश्किल

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज में कटौती से निवेशकों को लगेगी चपत?
हां 85.71%
नहीं 14.29%

बंदी से थमी कारों की बिक्री

उत्पादन ठप होने से मार्च में वाहनों की बिक्री 64 प्रतिशत घटी

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 1 अप्रैल

पहले से ही परेशान वाहन उद्योग की मुश्किलें कोरोनावायरस के बाद और बढ़ गई हैं। देश में लॉकडाउन के कारण ज्यादातर वाहन विनिर्माताओं के उत्पादन संयंत्र बंद हैं, जिससे वाहनों की बिक्री पर तगड़ा असर पड़ा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार वाहनों की बिक्री में औसतन 64 प्रतिशत तक की कमी आई है।

वाहनों की बिक्री के आंकड़े अर्थव्यवस्था की सेहत का अंदाजा लगाने में अहम माने जाते हैं और इनमें गिरावट से संकेत मिलता है कि हालात पटरी पर लाने के लिए बड़े उपायों की जरूरत है।

देश की सबसे बड़ी वाहन विनिर्माता कंपनी मारुति सुजूकी के बिक्री के आंकड़े पिछले साल के मुकाबले 47 प्रतिशत कम रहे हैं। हालांकि कंपनी ने कहा कि इन आंकड़ों की तुलना 2019 से नहीं की जा सकती है क्योंकि उसके संयंत्रों में 22 मार्च से उत्पादन ठप है।

घरेलू बाजार में हल्के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में भी 71.5 प्रतिशत की कमी आई और यह मार्च में वाहनों की संख्या 736 कारों की रह गई। मार्च 2019 में बिक्री का आंकड़ा 2,582 रहा था। कंपनी ने कहा कि मारुति सुजूकी कर्मचारियों की सुरक्षा एवं उनके हितों का पूरा ध्यान रख रही है। कंपनी मौजूदा हालात को देखते हुए कोरोनावायरस से निपटने में केंद्र एवं राज्यों के साथ सभी स्तरों पर सहयोगी करती रहेगी।

टाटा मोटर्स में अध्यक्ष (यात्री वाहन) मयंक पारीक ने कहा कि कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैलने और उसके बाद देश में लॉकडाउन लागू होने से वाहनों की बिक्री प्रभावित हुई है। कंपनी ने कहा कि मार्च में यात्री वाहनों की बिक्री में 68 प्रतिशत तक कमी आई है जबकि व्यावसायिक वाहनों की बिक्री 87 प्रतिशत तक घटी है। कंपनी ने कहा कि अनिश्चितता से बचने के लिए वह आने वाले समय में हरेक महीने के बजाय तिमाही आधार पर बिक्री के आंकड़े जारी करेगी। टाटा मोटर्स ने कहा कि इससे कंपनियों को दीर्घावधि को ध्यान में रखकर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा भी बिक्री में कमी से अछूती नहीं रही। सालाना आधार पर कंपनी के यात्री वाहनों की बिक्री मार्च में 88 प्रतिशत तक घट गई। आलोच्य महीने में कंपनी के यात्री वाहनों की बिक्री का आंकड़ा सालाना आधार पर 88 प्रतिशत कम होकर 3,384 कारों का रह गया। यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री में कमी इन आंकडों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रही। मार्च में कंपनी की एसयूवी की बिक्री 3,111 कारों की रही जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह संख्या 25,801 थी।

■ संबंधित खबर : पृष्ठ 3

वाहन कंपनियों की बिक्री का आंकड़ा

कंपनी	मार्च 2020	मार्च 2019	गिरावट (फीसदी में)
मारुति सुजूकी	83,792	1,58,076	46.99
टाटा मोटर्स	11,012	68,727	83.98
हुंडई	32,279	61,150	47.21
महिंद्रा	7,401	62,952	88.24
अशोक लीलैंड	1,787	20,521	91.29
वोल्वो आयशर	1,499	8,679	82.72
कुल	1,37,770	3,80,102	63.75

कोरोना की चिंता से लुढ़का बाजार

कोविड-19 के मामले बढ़ने और अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ने से घरेलू शेयर बाजार बुधवार को 4 फीसदी लुढ़क गया। एशियाई और यूरोपीय बाजारों में से 1 से 5 फीसदी की गिरावट आई है। सेंसेक्स 1,200 अंक गिरकर 28,265 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 344 अंक नीचे 8,254 पर बंद हुआ। विशेषज्ञों ने कहा कि लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों के ठप होने से कंपनियों के डिफॉल्ट होने तथा व्यापक स्तर पर छंटनी होने का भी खतरा बना हुआ है। इस हफ्ते बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। विदेशी निवेशकों ने 1,117 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की।

24 घंटे में 386 नए मामले, तीन की मौत

भाषा
नई दिल्ली, 1 अप्रैल

- **देश भर में संक्रमण के कुल 1,637 मामले, 38 की मौत**
- **पिछले 24 घंटों में 4,562 जांच, अब तक कुल 47,951 लोगों की हो चुकी है जांच**

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोनावायरस संक्रमण के 386 नए मामलों की पुष्टि और तीन लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में कोरोना संक्रमण के कुल 1,637 मामले हो गए हैं जबकि इस वायरस से मौत का आंकड़ा 38 तक पहुंच गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम के कारण कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि अकेले दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 18 मामलों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है जबकि तमिलनाडु में 65 नए मामले सामने आए हैं। अग्रवाल ने बताया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक में राज्यों के स्तर पर संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने के उपायों की समीक्षा की गई।

रेल मंत्रालय ने संदिग्ध मरीजों को पृथक रखने के लिये रेलगाड़ियों के डिब्बों को विशेष रूप से तैयार किया है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 4,562 परीक्षण किए गए और अब तक कुल 47,951 जांच हो चुके हैं।

प्रत्यक्ष कर संग्रह में रिकॉर्ड कमी

केंद्र सरकार ने 2019-20 में 9.98 लाख करोड़ रुपये कर संग्रह किया है। इसकी वजह से कर संग्रह के संशोधित अनुमान (आरई) की तुलना में 1.75 लाख करोड़ रुपये या 14.7 प्रतिशत की ऐतिहासिक कमी आई है। इस भारी अंतर के कारण वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग को वित्त वर्ष 2020-21 के बजट की पूरी गणित को बदलना पड़ सकता है। राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कर विभाग के इतिहास में अब तक इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं आई। इसकी प्रमुख वजह कुल मिलाकर आर्थिक मंदी, बजट के बाद कॉर्पोरेट कर में गिरावट की घोषणा, कर समाधान योजना विवाद से विश्वास तक शुरू न हो पाना और सबसे ज्यादा कोरोनावायरस के चलते हुई देशबंदी है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि प्रत्यक्ष कर के तहत 31 मार्च तक कुल सकल राशि 11.81 लाख करोड़ रुपये रही है। इसमें कर रिफंड करीब 183 लाख करोड़ रुपये है। कुल संग्रह से रिफंड के बाद शुद्ध कर संग्रह 11.7 लाख करोड़ रुपये पुनरीक्षित अनुमान की जगह 9.98 करोड़ रुपये रहा है। पृष्ठ 4

जीएसटी संग्रह पर कोरोना की मार

एजेंसियां
नई दिल्ली, 1 अप्रैल

- **चार महीने के अंतराल के बाद मार्च में एक लाख करोड़ रुपये कम रहा जीएसटी**
- **मार्च 2020 में 97,597 करोड़ रुपये रहा जीएसटी राजस्व**
- **देशव्यापी बंदी के कारण अगले महीने भी जीएसटी संग्रह में कमी का अंदेशा**

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के मनोवैज्ञानिक स्तर से पिछले चार महीने में पहली बार घटकर मार्च में 97,597 करोड़ रुपये रह गया। फरवरी में जीएसटी संग्रह 1.06 लाख करोड़ रुपये रहा था। कोविड-19 के कारण देश भर में बंदी और आर्थिक गतिविधियां ठप होने से कर संग्रह पर असर पड़ा है। मार्च 2020 में जीएसटी संग्रह पिछले साल मार्च की तुलना में 8.4 फीसदी कम रहा। हालांकि आने वाले महीने में भी जीएसटी संग्रह में कमी आएगी, क्योंकि मार्च के आंकड़े फरवरी में किए गए जीएसटी भुगतान पर आधारित हैं।

पिछले चार महीनों नवंबर से फरवरी के दौरान जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था। फरवरी में 1.05 लाख करोड़ रुपये संग्रह हुआ था।

मार्च में 76.5 लाख जीएसटी रिटर्न दाखिल किया गया, जो फरवरी के 83 लाख रिटर्न से कम है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'मार्च में सकल जीएसटी संग्रह 97,597 करोड़ रुपये रहा, जिनमें से सीजीएसटी 19,183 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 25,601 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 44,508 करोड़ रुपये और उपकर 8,306 करोड़ रुपये रहा।'

नियमित निपटारे के बाद मार्च 2020 में कुल सीजीएसटी राजस्व 41,901 करोड़ रुपये और एसजीएसटी 43,516 करोड़ रुपये रहा। मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी राजस्व में कमी घरेलू लेनदेन में कमी की वजह से हुई है। इसमें 4 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है।

वस्तुओं के आयात से होने वाला जीएसटी राजस्व भी मार्च 2019 की तुलना में 8 फीसदी घटा है। पूरे वित्त वर्ष 2019-20 में घरेलू स्तर पर जीएसटी संग्रह 8 फीसदी बढ़ा है। लेकिन आयात मद से जीएसटी संग्रह में इस दौरान 8 फीसदी की गिरावट आई है। कुल मिलाकर सकल जीएसटी राजस्व पिछले साल की तुलना में 4 फीसदी बढ़ा है।

सरकार ने केंद्रीय जीएसटी संग्रह का लक्ष्य 5.14 लाख करोड़ रुपये और मुआवजा उपकर 98,327 करोड़ रुपये रखा था। कर विशेषज्ञों का कहना है कि अगले महीने से जीएसटी संग्रह में खासी कमी आएगी। इससे सरकार के लिए जीएसटी संग्रह का लक्ष्य हासिल करना कठिन हो सकता है।

आरबीआई ने राहत का दायरा और बढ़ाया

अनूप राय
मुंबई, 1 अप्रैल

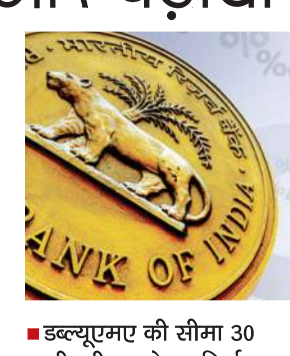

- **डब्ल्यूएमए की सीमा 30 फीसदी बढ़ाने का निर्णय**
- **निर्यातकों को निर्यात प्राप्तियों के लिए छह माह की मोहलत**

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए वेज ऐंड मीन्स एडवांसेज (डब्ल्यूएमए) सीमा 30 प्रतिशत बढ़ा दी है। बढ़ी हुई सीमा 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। आरबीआई ने निर्यातकों को भी राहत दी है और इसके तहत उन्हें निर्यात से आने वाली प्राप्तियों के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय दिया है। आरबीआई ने कोरोना से देश में पैदा हालत को देखते हुए ये कदम उठाए हैं।

केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि बैंकों को अगले एक साल के लिए काउंटरसाइक्लिकल कैपिटल बफर (सीसीवाईबी) भी सक्रिय करने की जरूरत नहीं है। इसका आशय यह है कि बैंक सुरक्षित रकम के रूप में रखी पूंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। निर्यात से जुड़े राहत पर आरबीआई ने कहा कि निर्यातकों को 31 जुलाई तक की निर्यात प्राप्तियों के लिए 15 महीने तक का समय दिया गया है। सामान्य नियमों के तहत निर्यातकों को इसके लिए 9 महीने का समय दिया जाता है। अब आरबीआई ने यह समयसीमा छह महीने के लिए बढ़ा दी है। इससे निर्यातकों को भविष्य में होने वाले निर्यात सौदे के लिए विदेशी खरीदारों के साथ बेहतर नियम शर्तें तय करने में आसानी होगी।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

कोविड-19 के इलाज के लिए तैयार बड़े अस्पताल

ज्योति मुकुल और ईशिता आयान दत्त
गुरुग्राम/कोलकाता, 1 अप्रैल

गुरुग्राम शहर में बंद पड़े हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास कुछ पुलिसवाले फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। उनमें से एक को बुखार है। उन्हें एक अलग रास्ते से ग्राउंड फ्लोर पर स्थित फ्लू क्लीनिक में भेजा जाता है। इस रास्ते से जाने वाले लोगों को अपनी कलाई पर ऑरेंज बैंड पहनना होता है।

अस्पताल में पहुंचने वाले हर व्यक्ति की पहले बुखार की जांच की जाती है और उसे अपनी यात्रा के इतिहास के बारे में जानकारी देनी होती है। जिन्हें बुखार की शिकायत नहीं होती है, उन्हें ग्रीन बैंड दिया जाता और बुखार, खांसी और सर्दी से पीड़ित मरीजों को ऑरेंज बैंड पहनना होता है। यहां तक कि अस्पताल में काम करने वालों को भी इस जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दुनियाभर में कहर बरपा रही कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए ये इंतजाम किए गए हैं।

दक्षिण कोलकाता के एएमआरआई अस्पताल में भी इसी तरह के नियमों का पालन किया जा रहा है। सुरक्षाकर्मी मरीजों और उनके परिजनों को एक मेज के पास ले जाते हैं जहां उनका उनके तापमान की जांच की जाती है। एएमआरआई और फोर्टिस देश के उन प्रमुख निजी अस्पतालों में शामिल हैं, जहां कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और इस बीमारी के संदिग्धों तथा मरीजों के इलाज के लिए समर्पित कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। फोर्टिस ने पूरे देश में अपने 20 अस्पतालों में 262 बिस्तरों के साथ आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। इन अस्पतालों में कोविड-19 के 83 संदिग्धों और 28 पॉजिटिव मरीजों का इलाज हो रहा है।

फोर्टिस और एएमआरआई दोनों अस्पतालों में 40 से 50 आयुवर्ग का एक-एक मरीज वेंटिलेटर पर है। एएमआरआई का मरीज एक गैर सरकारी संस्था में काम करता है जो झुग्गियों में भोजन के पैकेट बांटती है।

गुरुग्राम में फोर्टिस ने अब तक कोविड-19 के छह मरीज भर्ती किए हैं जिनमें से चार को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। इनकी उम्र 30 से 40 के बीच है। अस्पताल नें अपने कॉरपोरेट हेल्थ चेक अप एरिया हेल्थ4यू को फ्लू क्लीनिक में बदला है, जहां नमूने एकत्र किए जाते हैं और सामान्य परीक्षण किए जाते हैं। रात में यह काम बेसमेंट में स्थित क्वारंटाइन कक्ष में होता है।

फोटो : संजय शर्मा

- **अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए ग्रीन और ऑरेंज बैंड की व्यवस्था**
- **फोर्टिस और एएमआरआई ने बनाए अलग वार्ड**
- **अस्पताल आने वाले हर व्यक्ति की गहन जांच**
- **कर्मचारियों की भी हो रही है नियमित जांच**

फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जोनल डायरेक्टर डॉक्टर ऋतु गर्ग कहती हैं, 'अगर किसी व्यक्ति में कोविड-19 के संक्रमण का संदेह होता है तो उसे आपातकालीन आइसोलेशन वार्ड में ले जाया जाता है। कोविड-19 की जांच के लिए पहले नमूने सरकारी सिटी अस्पताल में भेजे जाते थे लेकिन अब उन्हें एसआरएल डायग्नोस्टिक में भेजा जाता है।

सरकार ने इस निजी लैब को कोविड-19 की जांच की अनुमति दी है जिसे लिए 4,500 रुपये की दर निर्धारित की गई है। अगर किसी मरीज में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि होती है तो उसे अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। निदेशक एवं पल्मोनरी यूनिट के प्रमुख डॉक्टर मनोज गोयल ने कहा, 'हम इसे कोरोना वार्ड नहीं कहते हैं बल्कि ईआर आइसोलेशन वार्ड और आइसोलेशन वार्ड कहते हैं।'

(शेष पृष्ठ 8 पर)

खबरों में रहे स्टॉक

बायोकॉन

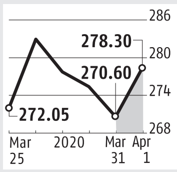

मलेशिया में इंसुलिन इकाई को यूएसएफडीए से ईआईआर मिली
₹ 270.60 पिछला बंद भाव
₹ 278.30 आज का बंद भाव
▲5.88 %

जिंदल स्टील ऐंड पावर

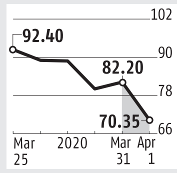

निफ्टी मेटल सूचकांक में गिरने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल
₹ 82.20 पिछला बंद भाव
₹ 70.35 आज का बंद भाव
▼14.42 %

ऐस्कॉर्ट्स

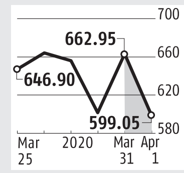

मार्च में ट्रैक्टर बिक्री 54 प्रतिशत घटकर 5,444 यूनिट रह गई
₹ 662.95 पिछला बंद भाव
₹ 599.05 आज का बंद भाव
▼9.64 %

पीवीआर

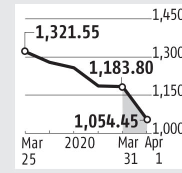

लंबे समय तक लॉकडाउन से मुनाफे पर पड़ सकता है दबाव
₹ 1,183.80 पिछला बंद भाव
₹ 1,054.45 आज का बंद भाव
▼10.93 %

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज

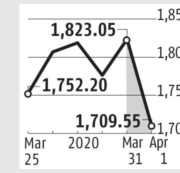

महज एक दिन में बाजार में 42,590 करोड़ रुपये का पूंजीकरण घटा
₹ 1,823.05 पिछला बंद भाव
₹ 1,709.55 आज का बंद भाव
▼6.23 %

संक्षेप में

विप्रो और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन देंगे 1,125 करोड़

कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, विप्रो और विप्रो एंटरप्राइजेज ने संयुक्त रूप से 1,125 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही यह भारतीय कॉरपोरेट घरानों द्वारा इस तरह के सबसे बड़े दान में से एक बन गया है। कुल रकम में से, विप्रो 100 करोड़ रुपये, जबकि विप्रो एंटरप्राइजेज 25 करोड़ रुपये देंगी। 1,000 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी रकम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा दिए जाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। समूह के अनुसार, इन संसाधनों से कोविड-19 महामारी से जूझ रहे चिकित्सा एवं सेवा समुदाय को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। *बीएस*

कोविड-19: टिकटॉक ने 100 करोड़ रुपये दिए

चीन के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने बुधवार को कहा कि वह भारत में डॉक्टरों और प्रमुख चिकित्सा स्टाफ की सुरक्षा के लिए 100 करोड़ रुपये मूल्य के 4,00,000 हजमत मेडिकल सूट और 2,00,000 मास्क दान में दे रही है। टिकटॉक ने एक बयान में कहा, 'भारत सरकार ने कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं और इस दान के जरिये हम इस प्रयास में योगदान देना चाहते हैं। टेक्स्टाइल मंत्रालय की मदद से यह जरूरी सामान भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपे जा रहे हैं।' बाइटडांस स्टार्टअप के स्वामित्व वाली टिकटॉक के भारत में 2 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं। *बीएस*

फोर्स मेजर क्लॉज को लेकर आशंकित हैं कंपनियां

सुरजीत दासगुप्ता, सुदीप्त दे और अभिषेक रक्षित
नई दिल्ली, 1 अप्रैल

मुंबई स्थित एक प्रमुख भारतीय व्यावसायिक घराने के चेयरमैन ने अपने प्रबंधकों को सभी अनुबंधों पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया है। इसकी वजह यह है कि वह नहीं चाहते कि उनका कोई विक्रेता 'फोर्स मेजर क्लॉज' के जरिये अनुबंध से बच निकलने की कोशिश करे।

उनकी इस चिंता की वजह भी है। शॉपिंग मॉल में अपमार्केट हाई स्ट्रीट रिटेलरों से लेकर फिल्म प्रदर्शनियों और सीमेंट, बिजली, ऊर्जा, लॉजिस्टिक, बंदरगाह, ऑटोमोबाइल्स तथा टायर उद्योग की कंपनियां अपनी सांविधिक देयताओं में किसी तरह की चूक से स्वयं को बचाने के प्रयास में इस क्लॉज पर अमल किए जाने की योजना बना रही हैं।

कंपनियां फरवरी में सरकारी अधिसूचना पर निर्भर कर रही थीं जिसमें कहा गया था कि कंपनियां इस क्लॉज का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि कोरोनावायरस को एक प्रमुख 'प्राकृतिक आपदा' के तौर पर समझा जा सकता है।

कॉरपोरेट और कानूनी विश्लेषक अभी भी इसे लेकर स्पष्ट स्थिति में नहीं हैं कि क्या इससे मदद मिलेगी। दिल्ली स्थित सलेक्ट सिटी वॉक के चेयरमैन अर्जुन शर्मा ने कहा, 'सभी श्रेणियों के ज्यादातर रिटेलर इस क्लॉज के परिणाम को लेकर चिंतित और आशंकित हैं। जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो हम इस पर विचार करेंगे। फिलहाल फोर्स मेजर की परिभाषा में यह महामारी शामिल नहीं है, क्योंकि किसी को इसकी आशंका नहीं थी।'

कानूनी विश्लेषक इसे लेकर सहमत हैं। निशीथ देसाई एसोसिएट्स में इंटरनैशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लीडर शमा ए लोया का कहना है कि ऐसी अधिसूचनाओं का सीमित प्रभाव देखा जा सकता है, वैसे यह फोर्स मेजर क्लॉज की सांविधिक भाषा और मामले की गंभीरता पर निर्भर करेगा।

हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि भारत में फोर्स मेजर सांविधिक अधिकार है, और कानून के तहत इसे सही तरीके से संहिताबद्ध नहीं किया गया है। डीएसके लीगल में पार्टनर अनुजा तिवारी का कहना है कि कई कंपनियां अपने अनुबंधों में इस क्लॉज को शामिल कर समय और लागत राहत पर ध्यान दे रही हैं।

हालांकि लगभग सभी विश्लेषक इसे लेकर सहमत हैं कि कोरोना महामारी का वायदा अनुबंधों पर बड़ा असर पड़ेगा। लोया ने कहा, 'भविष्य में कंपनियों को जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों, और ऐसी घटनाओं के प्रभाव जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों को शामिल करने के लिए अपने फोर्स मेजर क्लॉज में बदलाव लाने की जरूरत होगी।'

उदाहरण के लिए, सीमेंट उद्योग में कई कंपनियां इस क्लॉज का इस्तेमाल करने की योजना बना रही हैं। सीमेंट कंपनियों ने पेट कोक, क्लिंकर और जिप्सम के अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध किए हैं।

सीमेंट उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अल्पावधि में, पश्चिम एशियाई देशों, चीन, थाईलैंड से जिप्सम और क्लिंकर आयात स्थिर हो सकता है और हमारे आपूर्तिकर्ता हमसे खरीदारी अनुबंध पर अमल करने को कह सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो आपके पास फोर्स मेजर का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं रह सकता है।'

खबरों के अनुसार वाहन उद्योग में, हीरो मोटोकॉर्प और आयशर, दोनों ने इस क्लॉज पर अमल किया है। इसे लेकर राय अलग अलग है। मारुति सुजूकी के चेयरमैन आर सी भार्गव का कहना है, 'लॉकडाउन के दौरान मारुति उत्पादन नहीं कर रही है और इसलिए विक्रेताओं के मामले में कोई बिलिंग प्रक्रिया नहीं है। इसलिए हमारे लिए कोई समस्या नहीं है।'

कोविड-19 महामारी से बढ़ी चिंता

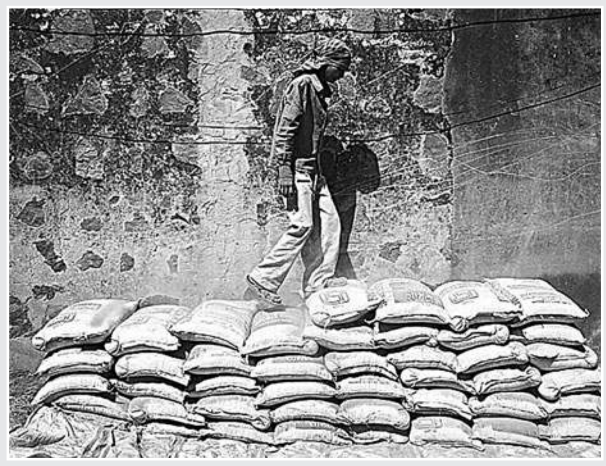

■ कॉरपोरेट और कानूनी विश्लेषक अभी भी इसे लेकर स्पष्ट स्थिति में नहीं हैं कि क्या इस क्लॉज से पूरी तरह मदद मिलेगी या नहीं

गेल द्वारा फोर्स मेजर लाने से बढ़ सकते हैं विवाद

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 1 अप्रैल

कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से कई ग्राहक कंपनियों ने फोर्स मेजर नियम लागू कर दिया है जिससे आखिरकार कई विवादों की शुरुआत होगी। उद्योग विशेषज्ञों तथा आखिरी छोर पर काम कर रही कंपनियों ने इस बात का अंदेशा जताया है। अधिकांश लोगों का मानना है कि इसे लेकर अंतिम निर्णय सरकार की ओर से आना चाहिए। गेल, इंडियन ऑयल और जीएसपीसी जैसी कई कंपनियों को अपनी ग्राहक कंपनियों से फोर्स मेजर संबंधी नोटिस मिल गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन नियमों के कारण परिचालन बंद हैं। इसी राह पर चलते हुए गेल ने भी अपनी आपूर्तिकर्ता, ओएनजीसी, ऑल इंडिया तथा पेट्रोनेट को इसी तरह का नोटिस भेज दिया है।

एक तेल उत्पादक कंपनी के वरिष्ठकार्यकारी अधिकारी ने कहा कि क्या कोरोना फोर्स मेजर नियमों के तहत आता है, यह विवादित विषय है। यह कोई प्राकृतिक आपदा या गैर-प्राकृतिक घटना नहीं है। उपभोक्ताओं ने पहले ही अपने तरीकों से इसकी व्याख्या कर ली। फोर्स मेजर भारत में अनुबंध का हिस्सा होता है जहां नियंत्रण से बाहर किसी परिस्थिति के चलते समयसीमा के तहत काम पूरा नहीं होने पर कंपनियां पेनल्टी से बच जाती हैं।

डेलॉयट में पार्टनर देवाशिष मिश्रा कहते हैं कि इससे विवादों को बढ़ावा मिलेगा। बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि संबंधित अनुबंध में फोर्स मेजर को किस तरह परिभाषित किया गया है। हालांकि अगर किसी एक कंपनी द्वारा इसे लागू किया गया तो उद्योग में दूसरी कंपनियां भी ऐसा करेंगी।लॉकडाउन के बाद मांग में भारी गिरावट आई है। उद्योग की रिपोर्टों के अनुसार, उर्वरक, बिजली और रिफाइनरी को छोड़कर अधिकांश कारखानों के बंद होने के कारण गैस की मांग में 15-20 प्रतिशत की गिरावट आई है। लक्ष्मीकुमार ऐंड श्रीधरन अटॉर्नी में पार्टनर एल बदरी नारायण कहते हैं कि फोर्स मेजर से जुड़ा अहम प्रश्न यह है कि क्या इसका इस्तेमाल करने वाला कारोबार या व्यक्ति इससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हुआ है? क्या यह प्रभाव इस स्तर का है जैसा संबंधित नियम में लिखा गया है? महामारी से प्रत्यक्ष तौर पर हुए सभी प्रभावों को फोर्स मेजर के तहत नहीं लाया जा सकता।

विलय पूरा, एचयूएल-जीएसके के समेकन पर जोर

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 1 अप्रैल

हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बुधवार को कहा कि उसने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का विलय पूरा कर लिया है, जिसके साथ ही उसका संयुक्त फूड एवं रीफ्रेशमेंट व्यवसाय बढ़कर 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया है। इस विलय से एचयूएल को हॉर्लिक्स और बूस्ट जैसे ब्रांडों तक पहुंच बनाने का भी मौका मिलेगा। एचयूएल भारत में हॉर्लिक्स ब्रांड के अधिकार खरीदने पर जीएसके पीएलसी को 3,045 करोड़ रुपये की रकम भी चुकाएगी और पैतृक यूनिलीवर को ब्रांड रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं जीएसके पीएलसी शेयर अदला-बदली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एचयूएल में अपनी 5.7 प्रतिशत शेयरधारिता बेचेगी।

बीएस बातचीत

15 दिन और बढ़ाई जाए लॉकडाउन की अवधि

आरपीजी समूह के अध्यक्ष **हर्ष गोयनका** लंबे समय तक के लॉकडाउन के लिए तैयार हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में हल्की मंदी का भी अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि सरकार ब्याज दरों के अलावा उद्योग की मदद के लिए दूसरे उपाय भी करेगी। गोयनका ने **सुरजीत दास गुप्ता** से कोरोनावायरस संकट पर बात की। पेश हैं बातचीत के संपादित अंश :

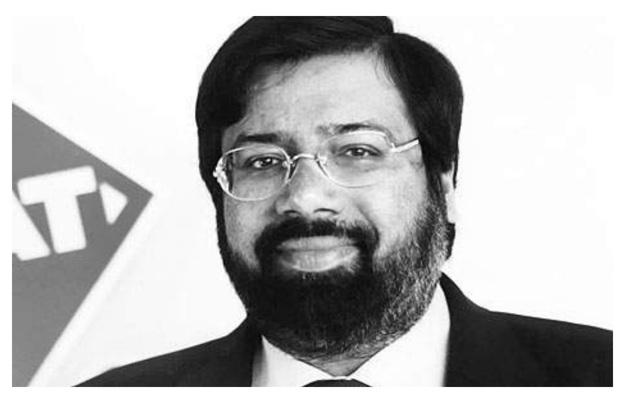

उद्योग पर इसके प्रभाव को देखते हुए क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी जारी रखना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि इसे जारी रखने से उद्योग तथा नौकरियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा?

मेरे उद्यमी मित्रों से मुझे अलग प्रतिक्रिया मिली है। मेरा मानना है कि इसे 15 दिन और जारी रखना चाहिए तथा इसके बाद एक-एक करके खोलना चाहिए। पहले चरण में आप 30 प्रतिशत कार्यबल को काम पर आने दीजिए और स्थिति को देखिए। मेरा मानना है कि सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन करके काफी समझदारी भरा निर्णय लिया है।

उद्योग पर आप किस तरह का प्रभाव देखते हैं? आपको अपने कारोबार से क्या उम्मीदें हैं?

हमारे जैसे कारोबार के लिए पहली तिमाही पूरी तरह से खराब रहेगी। हालांकि आपको कुछ निर्धारित लागत वहन करनी पड़ेगी। तेल की कीमतों में गिरावट से मार्जिन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां मांग की समस्या है। निर्यात पूरी तरह बंद है। हमारा मानना है कि दूसरी तिमाही में जाकर यह ठीक होगा। मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था हल्की मंदी से गुजरेगी।

आप उद्योग के लिए सरकार से किस तरह की सहायता की उम्मीद कर रहे हैं?

हम कर पर रोक तथा कार्यशील पूंजी सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। केवल सस्ती ब्याज दरों से काम नहीं चलेगा। सरकार को मांग पैदा करनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि बैंक आगे आए हैं। एसबीआई ने हमें कार्यशील पूंजी में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की पेशकश की है। दूसरे बैंक भी पूछ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे ऐसे सभी कारोबारियों के लिए कर रहे हैं।

आपके दूसरे कारोबार जैसे आईटी, ट्रांसमिशन तथा फार्मा आदि ने कैसा प्रदर्शन किया?

आईटी कारोबार में लोग घर से काम कर रहे हैं। हालांकि हमारे अधिकांश क्लाइंट अमेरिका से हैं और उनके ऊपर भी अतिरिक्त दबाव है। हम काम निरस्त होने या दोबारा बातचीत करने जैसे कदम की भी उम्मीद कर रहे हैं। ट्रांसमिशन कारोबार अच्छा चल रहा है। ऑर्डर बुक भरी हुई हैं जिसमें सरकार की भी अच्छी हिस्सेदारी है। उम्मीद है कि इसमें और अधिक धन आएगा। हालांकि हमारे पास डिलिवरी के लिए नौ महीने का ही समय है। फार्मा इस समय आवश्यक सेवाओं में शामिल है, लेकिन श्रमिकों की कमी के कारण यहां चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

कोविड-19 के बाद कारोबार कैसा होगा?

इसके बाद बहुत बड़ा बदलाव आएगा। 'ईसा पूर्व' तथा 'ईसा के बाद' जैसे बदलाव से इसकी तुलना की जा सकेगी। यह 'कोरोना से पहले' तथा 'कोरोना के बाद' की तरह होगा।

ड्राई बल्क, कंटेनर, ऑफशोर का परिदृश्य नकारात्मक : इक्रा

जहाजरानी के अहम क्षेत्रों मसलन ड्राई बल्क, कंटेनर और ऑफशोर का अल्पावधि का परिदृश्य नकारात्मक है क्योंकि कोविड-19 के प्रसार के कारण वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा। इक्रा ने आज एक बयान में यह जानकारी दी। इस प्रवृत्ति के अपवाद हालांकि तेल के टैंकर हैं, जहां तेल की कीमतों में तेज गिरावट ने मांग में इजाफा किया है और यह तेल की आपूर्ति और फ्लोटिंग स्टोरेज दोनों में देखा जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप टैंकर की दरों में खासा इजाफा हुआ है। *बीएस*

ज्यादा लाभांश वाले शेयर हो सकते हैं लोकप्रिय

उज्ज्वल जौहरी
नई दिल्ली, 1 अप्रैल

लाभांश एक ऐसा प्रमुख मानक बनी हुई है जिसे सुरक्षित निवेश की संभावना तलाशने वाले निवेशक गिरावट के दौरान शेयरों के चेयन के वक्त ध्यान में रखते हैं। तेजी के बाजार में, जब बाजार धारणा मजबूत हो, निवेशक अक्सर ऊंची शेयर कीमतों के जरिये पूंजी वृद्धि को ज्यादा तवज्जो देते हैं। हालांकि मंदी के दौरान लाभांश आय वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

निवेशक लाभांश प्रतिफल पर ध्यान देते हैं, जिससे कि उनके निवेश पर कुछ प्रतिफल सुनिश्चित किया जा सके, भले ही शेयर कीमत पर दबाव बना हुआ हो। ऊंचे लाभांश प्रतिफल से शेयरों के लिए गिरावट की स्थिति में भी मदद मिलती है।मौजूदा परिवेश में (अनिश्चितताओं का दबाव और सूचकांकों में भारी गिरावट) निवेशक ज्यादा लाभांश प्रतिफल वाले शेयरों पर विचार कर सकते हैं। दीर्घावधि (10 वर्ष) सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल गिरकर 6 प्रतिशत से नीचे रह जाने से सिर्फ ऊंचे लाभांश प्रतिफल वाले शेयर आकर्षक रह जाएंगे। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि जहां लाभांश प्रतिफल एक प्रमुख मानक है, इसे मौजूदा परिवेश में आय वृद्धि पर परिदृश्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए। येस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख अमर अंबानी का कहना है, 'ऊंचे लाभांश प्रतिफल वाले शेयरों पर केस-टु-केस आधार पर विचार करने की जरूरत होगी, क्योंकि कई शेयर आकर्षक निवेश दांव साबित नहीं हो सकते हैं।'

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयर मुनाफे की चिंता किए बगैर अपनी नेटवर्थ के 5 प्रतिशत लाभांश प्रतिफल के सरकार के निर्देश पर अमल कर रहे हैं।

इससे नकदी स्थिति में कमी को बढ़ावा मिला है। कंपनियों को ऋण देनदारियों में कमी लाने की भी जरूरत है। ओएनजीसी जैसी कंपनियों के लिए नकदी और नकदी समतुल्य निवेश 30 सितंबर 2019 को घटकर 6,700 करोड़ रुपये रह गया, जो वित्त वर्ष 2016 के अंत में 24,700 करोड़ रुपये था, जबकि शुद्ध उधारी समान अवधि के दौरान 21,500 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

विश्लेषकों का कहना है कि एक दिन बड़े लाभांश भुगतान की वजह से कंपनियों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। रिलायंस सिक्योरिटीज के बिनोद मोदी का कहना है कि जहां कोल इंडिया जैसे शेयर अच्छा लाभांश प्रतिफल दे रहे हैं, वहीं इस बाजार हालात में निवेशकों को मूल्यांकन पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी, और अनिश्चितताओं को देखते हुए शेयरों में मौजूदा स्तरों से गिरावट आ सकती है।

अच्छे शेयरों के चयन के प्रयास में कोटक सिक्योरिटीज में पीसीजी (प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप) के प्रमुख रसमिक ओजा का कहना है कि निवेशकों को मानकों के समावेश पर ध्यान देना चाहिए। मूल्यांकन, आय वृद्धि की उम्मीद, और संभावित तेजी पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसे शेयर उपलब्ध हैं जो कोविड-19 से कम प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उनमें अभी बड़ी गिरावट आई है।

भले ही बिजली की मांग बाद में घट गई है, लेकिन एनटीपीसी और पावरग्रिड जैसे शेयरों ने नियमित व्यवसायों से राजस्व का आश्वासन दिया है। ये कंपनियां अच्छी लाभांश आय भी दे रही हैं। जब मांग में सुधार आएगा, पूंजी में भी वृद्धि हो सकेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (रक्षा पर निर्भरता) और कोचीन शिपयार्ड जैसी कंपनियां भी तेजी के लिहाज से अच्छी स्थिति में बनी हुई हैं और अच्छा लाभांश प्रतिफल दे रही हैं।

ओजा का कहना है कि इसी तरह, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, और महानगर गैस तथा पेट्रोनेट एलएनजी जैसी गैस कंपनियां भी वृद्धि के मामले में मानक पूरा करती हैं और उनमें अच्छी तेजी की संभावना है। हालांकि, उनका कहना है कि निवेशकों के पोर्टफोलियो में निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल होनी चाहिए। उनके पसंदीदा शेयरों में फेडरल बैंक, टाटा केमिकल्स, आईटीसी, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, वेदांत, कैस्ट्रॉल और एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट शामिल हैं। इन कंपनियों ने मजबूत लाभांश प्रतिफल दिया है और इनमें अच्छी तेजी की संभावना है।

निवेश से पहले मूल्यांकन, आय वृद्धि, लाभांश भुगतान के रिकॉर्ड का रखें ध्यान

वैश्विक सूचकांकों में भारत का भारांक बढ़ाने का फैसला टला

एमएससीआई की तरफ से भारांक बढ़ाए जाने की उम्मीद थी क्योंकि सरकार ने देसी फर्मों में विदेशी निवेशकों की निवेश सीमा में इजाफा किया है

समी मोडक
मुंबई, 1 अप्रैल

एमएससीआई ने अपने वैश्विक सूचकांकों में भारत का भारांक बढ़ाने का फैसला टाल दिया है। उम्मीद की जा रही थी कि वैश्विक सूचकांक प्रदाता भारत का भारांक बढ़ाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने वस्तुत: देसी फर्मों में विदेशी निवेशकों की निवेश सीमा में इजाफा किया है।

अक्टूबर में सरकार ने परिपत्र जारी कर भारतीय कंपनियों में सांविधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सीमा 1 अप्रैल 2020 से बढ़ाकर क्षेत्रीय विदेशी निवेश सीमा तक तक कर दिया।

कई सूचीबद्ध कंपनियों ने क्षेत्रीय सीमा से काफी नीचे एफपीआई सीमा तय की है। ऐसे में नए ढांचे के तहत इन कंपनियों में निवेश की गुंजाइश स्वत: बढ़कर क्षेत्रीय सीमा तक हो गई। कई देसी बैंकों ने एफपीआई की सीमा 49 फीसदी तय की है जबकि विदेशी निवेश की क्षेत्रीय सीमा 74 फीसदी है। हालांकि सरकार ने कंपनियों को एफपीआई सीमा बोर्ड की मंजूरी के जरिये सीमित करने का विकल्प दिया है। इस वजह से इस पर अस्पष्टता है कि क्या एफपीआई निवेश की सीमा वास्तव में बढ़ी है।

एमएससीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा, यह परिपत्र हालांकि एफपीआई की सांविधिक सीमा क्षेत्रीय विदेशी निवेश सीमा तक बढ़ाता है, लेकिन यह कंपनियों को अपनी संबंधित एफपीआई सीमा को कम करने का विकल्प भी देता है, लेकिन इसके लिए कंपनी के निदेशक मंडल की मंजूरी 31 मार्च 2020 से पहले लेनी जरूरी है। एमएससीआई ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

इसमें कहा गया है कि एमएससीआई इन बदलावों के क्रियान्वयन और भारतीय प्रतिभूतियों पर लागू नई क्षेत्रीय सीमा के व्यवस्थित प्रकाशन तक इंतजार करेगा और उसके बाद ही एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव करेगा। अभी भारतीय बाजार के लिए तथाकथित एफआईएफ कम है क्योंकि वैश्विक बाजारों के मुकाबले यहां सार्वजनिक बाजार पूंजीकरण काफी कम है। भारत हालांकि वैश्विक स्तर पर पूर्ण बाजार पूंजीकरण के लिहाज से 10 अग्रणी बाजारों में शामिल है, लेकिन सार्वजनिक बाजार पूंजीकरण के लिहाज से उसका स्थान 13वां है।

कुछ विश्लेषक उम्मीद कर रहे थे कि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का भारांक 40 आधार बढ़ाया जाएगा क्योंकि एक अप्रैल से एफपीआई की सीमा में बदलाव प्रभावी हो जाएगा।

एमएससीआई ने कहा है कि वह अगस्त में तिमाही इंडेक्स समीक्षा से पहले स्थिति का दोबारा आकलन करेगा। हालांकि उसने कहा है कि वह इस संबंध में 30 जून तक आगे की सूचना उपलब्ध कराएगा। विशेषज्ञों ने कहा कि एफआईएफ में बढ़ोतरी से देसी बाजारों को मजबूती मिलेगी क्योंकि यह एफपीआई के निवेश में तीव्र इजाफा करेगा। भारतीय बाजार विदेशी फंडों की निकासी का सामना कर रहा है। मार्च में एफपीआई की कुल निकासी करीब 60,000 करोड़ रुपये रही, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है।

इस बीच, एमएससीआई ने विदेशी स्वामित्व की सीमा की गणना में डिपॉजिटरी रिसीट्स को बनाए रखने की अनुमति देकर कुछ राहत दी है। एक साल पहले उसने डिपॉजिटरी रिसीट्स को अलग रकने का प्रस्ताव किया था, जिससे टाटा मोटर्स, एलऐंडटी, आईटीसी और डॉ. रेड्डीज जैसी कंपनियों से निवेश निकासी की चिंता बढ़ा दी थी। एमएससीआई ने कहा है कि वह भारतीय प्रतिभूतियों में विदेशी स्वामित्व की सीमा की गणना में डिपॉजिटरी रिसीट्स को बनाए रखेगा। कई लोगों को लग रहा था कि अगर एमएससीआई डिपॉजिटरी रिसीट्स को इससे अलग करता है तो भारत का कुल भारांक 25 आधार अंक घट जाएगा।

थोड़ा फायदा, थोड़ा नुकसान

- सरकार ने एफपीआई निवेश की सीमा क्षेत्रीय सीमा तक बढ़ाने का किया फैसला
- यह कदम एफपीआई के लिए निवेश की गुंजाइश बढ़ाने के लिए उठाया गया था
- इसके परिणामस्वरूप एमएससीआई की तरफ से भारत का भारांक बढ़ाने की उम्मीद थी
- इंडेक्स प्रदाता ने कहा कि वह और स्पष्टता तक इंतजार करेगा

मार्च में घटी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 1 अप्रैल

देश में वाणिज्यिक वाहन उद्योग में मार्च के महीने में बिक्री में गिरावट जारी रही, जिसकी वजह कोरोनावायरस का प्रसार और बीएस-6 की ओर बढ़ने की योजना रही। पूरे वित्त वर्ष में प्रमुख कंपनियों की देसी बिक्री में गिरावट की प्रवृत्ति बनी रही, हालांकि टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों की खुदरा बिक्री बढ़ी।

टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहनों की देसी बिक्री मार्च 2020 में 90 फीसदी घटकर 5,336 वाहन रह गई, जो मार्च 2019 में 50,917 वाहन थी। मध्यम व भारी वाहनों की बिक्री 90 फीसदी घटकर 1,601 वाहन रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 15,327 वाहन रही थी। पूरे साल में देसी बिक्री 34 फीसदी घटकर 3,10,855 वाहन रह गई, जो इससे पिछले साल 4,68,692 वाहन रही थी। हालांकि इस अवधि में मध्यम व भारी वाहनों की बिक्री 50 फीसदी घटकर 75,485 वाहन रह गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 1,51,105 वाहन रही थी।

टाटा मोटर्स के अध्यक्ष (वाणिज्यिक वाहन कारोबारी इकाई) गिरीश वाघ ने कहा, मार्च 2020 में देसी बिक्री 5,336 वाहन रही, जिस पर कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन और बीएस-6 की ओर बढ़ने की योजना का असर पड़ा। खुदरा बिक्री हालांकि थोक से काफी आगे रही। पूरे साल हुई बिक्री के मुकाबले खुदरा बिक्री 16 फीसदी ज्यादा रही।

बीएस-4 के करीब-करीब सभी वाहनों की खुदरा बिक्री हो चुकी है, हालांकि कुछ पंजीकरण का इंतजार कर रहे हैं जो लॉकडाउन के चलते रुक गया है। बीएस-6 वाहनों का उत्पादन पटरी पर है और कंपनी ने शुरुआती उत्पादन की थोक बिक्री की है।

मार्च 2020 में अशोक लीलैंड की देसी बिक्री 91 फीसदी घटकर 1,787 वाहन रह गई, जो एक साल पहले 20,521 वाहन रही थी। मध्यम व भारी ट्रकों की अगुआई में यह गिरावट आई क्योंकि यह 93 फीसदी घटकर 899 वाहन रह गई, जो एक साल पहले 13,134 वाहन रही थी, वहीं बसों की बिक्री 71 फीसदी घटकर 599 रह गई, जो एक साल पहले 2,101 वाहन रही थी। हल्के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 95 फीसदी घटकर 298 वाहन रह गई।

देसी मध्यम व भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री मार्च 2020 में समाप्त वर्ष में 46 फीसदी घटकर 71,421 वाहन रह गई, जो एक साल पहले 1,31,936 वाहन रही थी। मध्यम व भारी वाणिज्यिक ट्रकों की बिक्री 54 फीसदी घटकर 53,266 वाहन रह गई। वाणिज्यिक वाहनों की कुल देसी बिक्री 37 फीसदी घटकर 1,16, 333 वाहन रही।

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में माह के दौरा3न 90 फीसदी की गिरावट आई और कुल बिक्री 2,325 रह गई। पूरे साल में बिक्री 20 फीसदी घटकर 1,99,135 वाहन रही, जो इससे पिछले साल 2,48,601 रही थी। महिंद्रा के मध्यम व भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री मार्च में 100 फीसदी घटकर 4 वाहन रह गई।

आयशर मोटर्स के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 81 फीसदी घटकर मार्च में 1,409 वाहन रही, जो पहले 7,329 वाहन रही थी। वोल्वो का निर्यात 95 फीसदी घटा। कुल बिक्री 83 फीसदी घटकर 1,499 रह गया। मार्च में समाप्त वर्ष में आयशर का देसी कारोबार 30.3 फीसदी घटकर 43,046 रह गया।

नॉर्वे के सॉवरिन फंड की बिकवाली से घबराहट

समी मोडक
मुंबई, 1 अप्रैल

तेल की कीमतों में गिरावट के कारण सरकारी राजस्व में हुई कमी की भरपाई के लिए नॉर्वे सॉवरिन वेल्थ फंड (एसडब्ल्यूएफ) की तरफ से अपनी हिस्सेदारी की बिकवाली की योजना से संबंधित रिपोर्ट से देसी निवेशकों के बीच घबराहट देखने को मिली।

तेल समृद्ध देश दुनिया के सबसे बड़े एसडब्ल्यूएफ का परिचालन करता है और उसकी परिसंपत्तियां करीब 1 लाख करोड़ डॉलर की है। इस साल तेल की कीमतें 60 फीसदी घटी हैं, ऐसे में यह देश अपने इतिहास में सबसे खराब आर्थिक प्रदर्शन का सामना कर रहा है, जो उसे अपने फंडों से निकासी के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में ये बातें कही है। नॉर्वे सरकार का पेंशन फंड ग्लोबल भारतीय बाजार में बड़ा निवेशक है और परिसंपत्तियां करीब 10 अरब डॉलर की है। पिछले महीने किए गए सालाना खुलासे के मुताबिक, फंड के कुल इक्विटी निवेश में भारत की हिस्सेदारी 1.2 फीसदी है। फंड की शेयरधारिता ब्लूचिप कंपनियों मसलन रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी जैसी फर्मों में है। इसके अलावा देसी डेट व रियल एस्टेट में उसका निवेश 2 अरब डॉलर से ज्यादा है। जियोजित फाइनैंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, अगर ऐसे बड़े फंड को बिकवाली करनी पड़ रही है तो यह न सिर्फ भारत के लिए बड़ी चिंता होगी बल्कि वैश्विक बाजारों के लिए भी। बाजार के विशेषज्ञों ने कहा कि तेल की कीमतों में गिरावट ने वैश्विक इक्विटी के सामने बड़ा जोखिम पेश किया है क्योंकि तेल समृद्ध देशों की तरफ से परिचालित फंड दुनिया भर में बड़े निवेशक हैं।

एनबीएफसी को एएलएम पर दबाव की आशंका

बीएस सवाददाता
मुंबई, 1 अप्रैल

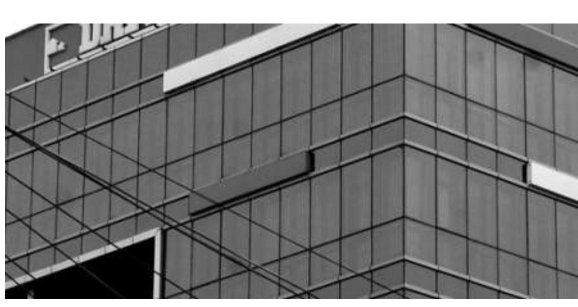

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सभी तरह के ऋणों पर तीन महीने की रोक के निर्णय का ऋणदाताओं द्वारा स्वागत किया गया था। लेकिन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को अपनी अल्पावधि देनदारियां चुकाने की राह में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि ऋणदाता इस अवधि के दौरान प्राप्त ब्याज (ग्राहकों से) को आय के तौर पर दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आय (जिससे उनका लाभ और नुकसान का विवरण प्रभावित नहीं होगा), ऋण ईएमआई पर रोक की वजह से नकदी प्राप्ति का प्रवाह नहीं होगा। इसका एनबीएफसी के नकदी प्रवाह पर प्रभाव पड़ेगा, उनके परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) पर दबाव बढ़ेगा। ज्यादा प्रभाव एक-तीन महीने के एएलएम पर पड़ेगा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि नकदी प्रवाह पर दबाव बना रहा तो 6 महीने तक के लिए एएलएम प्रभावित हो सकता है।

क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक अजीत वेलोनी का कहना है, 'जहां ईएमआई पर रोक से परिसंपत्ति के संदर्भ में कुछ राहत मिली है, वहीं देनदारियों को लेकर एनबीएफसी के लिए चुनौतियां पैदा हुई हैं।' बजाज फाइनैंस और एचडीएफसी जैसी एनबीएफसी अपनी देनदारियों का 45-47 प्रतिशत बाजार योजनाओं के जरिये पूरा करती हैं। एलऐंडटी फाइनैंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा फाइनैंशियल सर्विसेज जैसी कंपनियां अपनी 48-53 प्रतिशत वित्तीय जरूरत पूरी करने के लिए बॉन्डों और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स पर जोर देती हैं।

एएलएम असमानता को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एनबीएफसी डेट योजनाओं के लिए बढ़ रही बैंकों/संस्थानों की निवेश भूख को देखते हुए 1 लाख करोड़ रुपये के दीर्घावधि रीपो ऑपरेशंस की योजना तैयार की है। हालांकि, एक एएमसी के प्रमुख (फिक्स्ड इनकम) के अनुसार म्युचुअल फंड लिक्विड फंडों की वैल्यू में मौजूदा गिरावट को देखते हुए एनबीएफसी की निवेश योजनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम इस श्रेणी में रिडम्पशन दबाव में इजाफा देख रहे हैं। इसने हमें एनबीएफसी की योजनाओं में जोखिम लेने से सीमित किया है।' फंड प्रबंधकों का कहना है कि पिछले 9 महीनों के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए उनकी दिलचस्पी घटी है।

वित्त वर्ष 2020 में बॉन्ड, मुद्रा बाजारों में रहा काफी उतारचढ़ाव

रुपये ने 76.30 प्रति डॉलर का निचला स्तर छू लिया, वहीं 10 साल के बॉन्ड का प्रतिफल 6 फीसदी रह गया

अनूप रॉय
मुंबई, 1 अप्रैल

GOING DOWNHIL
₹ vs $ (inverted scale)

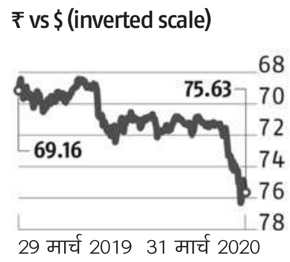

G-SEC 10-YR YIELDS
(%)

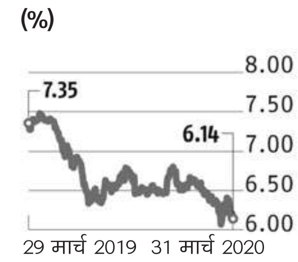

बॉन्ड और मुद्रा बाजारों के लिए काफी उतारचढ़ाव वाला साल रहा क्योंकि कोरोनावायरस महामारी के डर से बाजार करीब-करीब थम गए। रुपये ने जहां करीब 76.30 प्रति डॉलर का अब तक का निचला स्तर छू लिया, वहीं 10 साल के बॉन्ड का प्रतिफल घटकर 6 फीसदी रह गया क्योंकि कोविड-19 के कारण दुनिया भर की वित्तीय परिसंपत्तियों में अप्रत्याशित गिरावट देखने को मिली। जब प्रतिफल गिरता है तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं और इसी तरह जब प्रतिफल बढ़ता है तो बॉन्ड की कीमतें घटती हैं।

रुपये ने वित्त वर्ष 2019-20 की समाप्ति 75.6 प्रति डॉलर पर की और 10 वर्षीय प्रतिफल 6.1 फीसदी पर बंद हुआ। साल के शुरुआत में रुपया व बॉन्ड का प्रतिफल क्रमश: 69.2 प्रति डॉलर और 7.4 फीसदी रहा। बॉन्डों में तेजी आई, उसकी वजह यह रही कि निवेशकों ने शेयर बेचकर रकम निकाला और उसे फिक्स्ड इनकम वाली प्रतिभूतियों में लगाया। साल के आखिर में सरकार ने भी विदेशी निवेशकों को बिना किसी सीमा के पांच विशेष बॉन्डों में निवेश की अनुमति दे दी, जो 2024 से 2049 के बीच परिपक्व होंगे।

एचएसबीसी ने कहा, इससे आगामी 12-18 महीने में वैश्विक बॉन्ड इंडेक्स में उसे शामिल किया जा सकता है। बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है, ब्लूमबर्ग-बार्कलेज ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल किए जाने से 6-7 अरब डॉलर का संभावित निवेश हो सकता है। हालांकि यह विदेशी निवेशकों का मूड शायद ही बदल सकता है, जो बॉन्ड बाजार में शुद्ध बिकवाल बने हुए हैं।

बैंक ने कहा है, मध्यम अवधि के लिहाज से भारत को इंडेक्स में शामिल किए जाने की संभावना सकारात्मक प्रगति है, लेकिन विदेशी बिकवाली के मौजूदा माहौल में यह तत्काल राहत शायद ही दे पाएगा। विदेशी निवेशकों ने पिछले छह हफ्तों में भारतीय बॉन्ड से करीब 9.5 अरब डॉलर निकाले हैं।

केंद्रीय बैंकों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों की निकासी की क्षतिपूर्ति के लिए और बॉन्ड का प्रतिफल नरम बनाए रखने के लिए नकदी झोंकने के कई कदम लागू किए हैं। मार्च में ही आरबीआई की तरफ से 6.5 लाख करोड़ रुपये की नकदी झोंकी गई है, जो जीडीपी का 3.2 फीसदी है। इसमें लॉन्ग टर्म रीपो परिचालन के तहत 1 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसे खास तौर से कॉरपोरेट बॉन्ड को सहारा देने के लिए किया गया। कॉरपोरेट बॉन्ड का प्रतिफल तेजी से घटा।

रुपया समेत उभरते बाजारों की मुद्राओं में डॉलर के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ है और आने वाले समय में तेल की नरम कीमतें रुपये की मदद करेगी। लेकिन यह उस पर निर्भर करेगा कि कोविड-19 का डर कितनी तेजी से खत्म होता है।

डीलरों ने कहा, इस समय करेंसी पर मजबूत कॉल लेना संभव नहीं है। अगले हफ्ते रुपये को 75.15 व 75.65 के बीच सहारा मिलेगा। लेकिन डॉलर में संभावित तेजी गणित बिगाड़ सकता है।

आईएफए ग्लोबल ने कहा है, लाइबोर अभी भी उच्चस्तर पर है जबकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने नकदी झोंकी है। फॉरेक्स बाजारों में यह दबाव अभी प्रतिबिंबित नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर इश पर नजर रखनी होगी।

मुद्रा के उतारचढ़ाव पर लगाम कसने के लिए आरबीआई के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, ऐसे में वह काफी डॉलर भी झोंक रहा है। उदाहरण के लिए 20 मार्च को समाप्त हफ्ते में आररबीआई ने मुद्रा को स्थिर करने के लिए 12 अरब डॉलर बेचे।

जून के बाद भारतीय बैंक अपनी विदेशी शाखाओं के जरिये ऑफशोर बाजारों में भागीदारी कर सकते हैं। यह आरबीआई के लिए ऐसे बाजारों मे हस्तक्षेप के लिए पूरी तरह से नया गंतव्य खोलेगा। करेंसी डीलरों के मुताबिक, यह काफी हद तक विनिमय दर के उतारचढ़ाव में कमी ला सकता है।

बीएस बातचीत

कोविड-19 के कारण एक अंक में रहेगी हमारी बढ़त की रफ्तार

कोरोनावायरस के कारण भारत में सोशल डिस्टेंसिंग चलन में है, ऐसे में जीवन बीमा कारोबार पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है क्योंकि इस कारोबार के लिए आमने-सामने बातचीत जरूरी होती है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी **प्रशांत त्रिपाठी** ने **सुब्रत पांडा** को दिए साक्षात्कार में बताया कि कैसे यह क्षेत्र प्रभावित होगा, कंपनी की रणनीति में कैसे बदलाव होगा। साथ ही ऐक्सिस बैंक के साथ संभावित सौदे पर भी उन्होंने विस्तार से बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश...

मौजूदा लॉकडाउन की स्थिति के लिए आपने कैसे तैयारी की क्योंकि जीवन बीमा कारोबार में आमने-सामने बातचीत की दरकार होती है?

यह अनुमान लगाते हुए हमने काफी पहले तैयारी शुरू कर दी थी कि इस तरह का कुछ होगा। हमारे ज्यादा कर्मी घर से काम कर रहे हैं। अब हर कोई कनेक्टेड है और हम 80 फीसदी क्षमता पर काम करने में सक्षम हैं, जो खराब नहीं है क्योंकि लेनदेन की संख्या घटी है। हम अपनी बिक्री प्रक्रिया का हरसंभव डिजिटलीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और ग्राहकों तक भी डिजिटल तरीके से पहुंचने की। हालांकि यह आमने-सामने होने वाली बिक्री की तरह नहीं होगी। लेकिन समय के साथ यह और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा।

इस लॉकडाउन का क्या असर होगा?

मार्च में काफी लोग जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं और अचानक लॉकडाउन होने से हमें उद्योग पर कुछ असर की आशंका है। क्लेम में बढ़ोतरी अभी नहीं हुई है क्योंकि भारत में मरने वालों की संख्या अभी तक बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में जब तक भारत में यह महामारी बड़ी नहीं बन जाती, हमें इस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं दिख रहा। कंपनी के लिहाज से हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान कर रहे हैं कि हमारी वित्तीय स्थिति सुरक्षित रहे।

इक्विटी बाजारों के उतारचढ़ाव को देखते हुए क्या आपके सॉल्वेंसी मार्जिन पर असर पड़ेगा?

मुझे लगता है कि हमारा सॉल्वेंसी मार्जिन ठीक है। इसमें 150 फीसदी की अनिवार्यता है और हमारा आंतरिक लक्ष्य 170 फीसदी का रहा है जबकि हम 200 फीसदी से ऊपर हैं। ऐसे में हम अभी सुरक्षित हैं। इक्विटी बाजार में निवेश का हमारा बड़ा हिस्सा यूलिप में है, जो हमेशा ही मार्क-टु-मार्केट रहता है और पूंजी में उसका प्रवाह नहीं होता। इसलिए उसका असर नहीं पड़ने जा रहा।

मैक्स लाइफ में ऐक्सिस बैंक कितनी हिस्सेदारी लेगा?

हमने करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत तीन पक्षकारों मैक्स फाइनैंशियल, मैक्स लाइफ और ऐक्सिस बैंक कुछ ऐसा ढांचा बना रहे हैं जो लंबी अवधि के लिए, रणनीतिक है और उसमें इक्विटी शामिल होगी। अभी ऐक्सिस बैंक के पास मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की करीब 2 फीसदी हिस्सेदारी है और उसे और ऊपर ले जाने का है ताकि वे वैल्यू के सृजन में बेहतर तरीके से भागीदारी कर सके।

आपके लिए साल कैसा रहा?

इस साल को दो भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है - 24 मार्च तक और उसके बाद। हम फरवरी तक बेहतर कर रहे थे और सालाना आधार पर 17-18 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन साल समाप्त होने पर हमारा मानना है कि यह एक अंक में रहने वाला है। मौजूदा स्थिति न सिर्फ हमारे लिए निरंतरता अवरोध पैदा कर रहा है बल्कि उद्योग में हर किसी के लिए। कोविड-19 का प्रकोप न होता तो हमारे पास आक्रामक योजना थी, जिसमें 20 फीसदी की बढ़त का लक्ष्य था।

स्मार्टफोन बाजार 2020 में बना रह सकता है सपाट

निर्माताओं ने बिक्री पर प्रभाव का आकलन अभी नहीं किया है

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 1 अप्रैल

देश का मजबूत स्मार्टफोन बाजार भी कोविड-19 महामारी की वजह से बुरे दौर से गुजरने की राह पर बढ़ रहा है। चूंकि ज्यादातर निर्माता अभी भी अपने व्यवसाय पर इस महामारी के प्रभाव का आकलन करने में लगे हुए हैं, लेकिन शुरुआती अनुमानों से संकेत मिलता है कि यह बाजार 2020 में अपनी सबसे कम दर से बढ़ सकता है।

आईडीसी इंडिया के अनुमानों के अनुसार, स्मार्टफोन बिक्री सपाट बने रहने की आशंका है। अन्य उद्योग विश्लेषकों और बाजार शोध कंपनियों ने वृद्धि दर 5 प्रतिशत से नीचे बने रहने का अनुमान जताया है, जो पिछले खराब प्रदर्शन की तुलना में भी बदतर है।

भारत में स्मार्टफोन बिक्री हमेशा से दो अंक में रही है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2012 में यह बाजार सभी प्रमुख बाजारों में 3जी सेवा की शुरुआत के साथ 120 प्रतिशत बढ़ा था। हाल के वर्षों के दौरान वृद्धि दर में आई गिरावट और मंदी के बावजूद 2019 में बिक्री 10 प्रतिशत बढ़ी। अब तक सबसे खराब समय 2016 में देखा गया, जब नोटबंदी से इस उद्योग की वृद्धि 6 प्रतिशत पर थी।

हालांकि वर्ष 2020 में, कलपुर्जा आपूर्ति के अभाव में फरवरी से सभी प्रमुख विक्रेताओं की निर्माण योजनाएं प्रभावित हुईं। लॉकडाउन ने चिंता और बढ़ा दी है और बाजार अब पूरी तरह ठप हो गया है।

आईडीसी में शोध निदेशक नवकेंदर सिंह के अनुसार, 2020 की पहली छमाही के दौरान बिक्री बुरी तरह से प्रभावित होगी। शोध एजेंसी साइबरमीडिया (सीएमआर) ने 2020 के लिए अपना बाजार अनुमान संशोधित किया है। उसने कहा है कि स्मार्टफोन निर्माण जनवरी-जून से घटकर 38-40 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है।

सीएमआर के प्रमुख (इंडस्ट्री इंटेलीजेंस ग्रुप) प्रभु राम ने कहा, 'हमें चालू वर्ष 2020 की पहली तिमाही में मोबाइल शिपमेट में सालाना आधार पर लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है।'

कई प्रमुख मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि अभी इस महामारी के निर्णायक प्रभाव का आकलन किया जाना बाकी है। हालांकि कुछ निर्माता जुलाई के बाद से हालात में सुधार की उम्मीद जता रहे हैं।

आईडीसी और सीएमआर जैसे बाजार विश्लेषकों को वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान कुछ वृद्धि का अनुमान है।

संक्षेप में

चीनी उत्पादन में 22 प्रतिशत गिरावट

भारत का चीनी उत्पादन मार्च अंत में लगभग 233 लाख टन रहा जो एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 22 प्रतिशत घटकर कम है। गन्ना उत्पादन कम होने से चीन मिलों का काम प्रभावित हुआ है। चीनी उद्योगों के प्रमुख संगठन, भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारत ने वर्ष 2018-19 में 330 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन किया था लेकिन वर्ष 2019-20 में उत्पादन घटकर 260 लाख टन रहने का अनुमान है। *भाषा*

कांग्रेस ने पुरानी ब्याज दर बहाल करने की मांग की

कांग्रेस ने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और लोक भविष्य निधि समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कम करने के फैसले को संवेदनहीन और मूर्खतापूर्ण करार देते हुए बुधवार को कहा कि अगले तीन महीने के लिए पुरानी ब्याज दर बहाल करनी चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट किया, 'पीपीएफ और लघु बचत पर ब्याज दर कम करने के लिए यह गलत समय था।' *भाषा*

राज्यों ने रोकी अक्षय ऊर्जा खरीद, टाला भुगतान

श्रेया जय
नई दिल्ली, 1 अप्रैल

देशबंदी और बिजली की मांग में गिरावट को देखते हुए कुछ राज्यों ने अक्षय ऊर्जा खरीद में कटौती की है और अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को भुगतान न करने को लेकर नोटिस जारी किए हैं। इन राज्यों ने अपने बिजली खरीद समझौते (पीपीए) में फोर्स मेजर प्रावधान का इस्तेमाल किया है।

पंजाब सरकार ने अक्षय ऊर्जा उत्पादकों से अपनी लागत और जोखिम पर इकाइयां चलाने को कहा है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश ने भुगतान करने से इनकार कर दिया है और उन्हें अक्षय ऊर्जा खरीद में कटौती करने को कहा है।

अक्षय ऊर्जा में सौर, पवन, छोटी पनबिजली और बॉयोमास उत्पादन आता है। ये निश्चित रूप से चलने वाली श्रेणी में आते हैं, जिसका मतलब यह है कि किसी भी स्थिति में इन्हें रोका या बंद नहीं किया जा सकता है।

बहरहाल पंजाब ने राज्य को बिजली आपूर्ति करने वाले कुछ अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को नोटिस भेजा है कि वह बिजली खरीद में उत्पादन में कमी करेगा। फोर्स मेजर प्रावधान के तहत राज्य ने बिजली उत्पादकों से कहा है कि वे अगर राज्य के ग्रिड को बिजली देते हैं तो वह उनके जोखिम और उनकी लागत पर होगा।

आपूर्ति में फोर्स मेजर प्रावधान या परियोजना चालू करने के प्रावधान में तमाम वजहें और परिस्थितियां दी गई हैं, जो मानव के नियंत्रण से बाहर हैं। बहरहाल इस नियम में किसी पक्ष को पूरी तरह से हटने का प्रावधान नहीं है, बल्कि इस नियम को कुछ समय के लिए रद्द कर दिया जाता है।

पंजाब राज्य बिजली निगम (पीएसपीसीएल) ने सोमवार को बिजली उत्पादकों को भेजे नोटिस में कहा है, 'आपको सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के संकट को देखते हुए फोर्स मेजर प्रावधान के तहत पीएसपीसीएल खरीद की अपनी बाध्यता तत्काल प्रभाव से महामारी समाप्त होने तक के लिए खत्म कर रही है। इस अवधि के दौरान अगर कोई बिजली पीएसपीसीएल या पीएसटीसीएल सिस्टम को भेजी जाती है तो यह आपके जोखिम और आपकी लागत पर होगी।'

बिजनेस स्टैंडर्ड ने हाल ही में खबर प्रकाशित की थी कि मार्च के दौरान बिजली की मांग 31 प्रतिशत कम हो गई है, जबकि क्षमता में 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसने फोर्स मेजर और राजस्व घटने की वजह से भुगतान करने में सक्षम न होने के कारण सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भुगतान करने से इनकार कर दिया था। भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) ने इससे जुड़े आवेदन खारिज कर दिया था।

एसईसीआई नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आता है और उत्तर प्रदेश को अक्षय बिजली की आपूर्ति करता है। उसने कहा है कि वित्त या कोष की अपर्याप्तता बिल भुगतान में अक्षमता को फोर्स मेजर नहीं बताया जा सकता है, जिसकी वजह से अक्षय ऊर्जा कंपनियां जैसे एजर पावर, रिन्यू पावर, सॉफ्टबैंक एनर्जी और हीरो फ्यूचर एनर्जी संकट में फंस रही हैं, जो उत्तर प्रदेश क बिजली की आपूर्ति करती हैं।

मध्य प्रदेश देश का प्रमुख अक्षय ऊर्जा उत्पादक राज्य है, उसने सभी अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को नोटिस भेजा है कि पीपीए के तहत वह बाध्यताएं पूरी करने में सक्षम नहीं है क्योंकि बिजली बिल संग्रह से आने वाले राजस्व में बहुत कमी आई है। राज्य ने यह भी कहा है कि वह चूक की अवधि भी तय नहीं कर सकता। उसने भी फोर्स मेजर प्रावधानों का इस्तेमाल किया है।

अक्षय ऊर्जा उत्पादकों के कुछ समूहों ने अब केंद्र से अनुरोध किया है कि वह वह राज्यों को अक्षय ऊर्जा की शिड्यूलिंग व भुगतान के बारे में स्थिति साफ करे।

केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने पिछले सप्ताह बिजली वितरण कंपनियों को अनुमति दी थी कि वे बिजली उपभोक्ताओं की ओर से भुगतान में देरी को देखते हुए बिजली उत्पादन कंपनियों और पारेषण कंपनियों का भुगतान टाल सकती हैं।

राज्यों को धन के संकट से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का संकट गहराया

- राज्यों ने अपने बिजली खरीद समझौते में फोर्स मेजर प्रावधान का इस्तेमाल किया
- पंजाब सरकार ने अक्षय ऊर्जा उत्पादकों से अपनी लागत और जोखिम पर इकाइयां चलाने को कहा
- उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश ने भुगतान करने से इनकार कर दिया
- अक्षय ऊर्जा में सौर, पवन, छोटी पनबिजली और बॉयोमास उत्पादन आता है

रिजर्व बैंक ने राहतों का दायरा बढ़ाया, निर्यातकों को फायदा

पृष्ठ 1 का शेष...

निर्यातकों के संगठन फियो के अजय साहनी ने कहा कि उद्योग जगत ने आरबीआई से ऐसी रियायतों की मांग की थी।

साहनी ने कहा कि इससे निर्यातकों की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी।

उन्होंने कहा, 'यह रियायत निर्यातकों के लिए एक उपाय के तौर पर भी काम करती है। मांग कम होने पर ग्राहक साख की मांग करते हैं और अब निर्यातक बाद में प्राप्तियां हासिल करने के मकसद से यह मांग पूरी कर सकते है। इससे निर्यातकों को विदेशी बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलती है।'

हालांकि मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि आरबीआई को उन निर्यातकों के लिए भी कुछ कदम उठाना चाहिए था, जो फारवर्ड अनुबंध से जुड़े हैं। चूंकि, निर्यात प्राप्तियों की समय सीमा बढा दी गई है, इसलिए निर्यातकों के लिए फॉरवर्ड अनुबंध का कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन उन्हें अनुबंधों का पालन करना होगा। कारोबारियों के अनुसार इससे उन्हें नुकसान होगा। डब्ल्यूएमए एक अस्थायी नकदी व्यवस्था है, जिसके तहत केंद्र और राज्य आरबीआई से 90 दिनों तक के लिए उधार ले सकते है।

इससे उन्हें नकदी की किल्लत से निपटने में आसानी होती है। मंगलवार को आरबीआई ने केंद्र के लिए पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही के लिए डब्ल्यूएमए बढाकर 1.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया था। केंद्र के मामले में आरबीआई ने कहा था कि अगर सरकार डब्ल्यूएमए रकम के 75 प्रतिशत तक हिस्से का इस्तेमाल करता है तो यह बॉन्ड जारी कर सकता है।

जानकारों का कहना है कि डब्ल्यूएमए सीमा में बढ़ोतरी से राज्यों को बॉन्ड बाजार पर अधिक निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी।

वित्तीय जरूरतों के लिए राज्य बॉन्ड बाजार से उधार लेते हैं, लेकिन समतुल्य परिपक्वता वाले सरकारी बॉन्ड और राज्य के बॉन्ड के बीच अंतर 120 आधार अंक से अधिक हो गया है।

सामान्य परिस्थितियों में यह अंतर 40 से 60 आधार अंक रहता है। राज्यों ने बॉन्ड बाजार से उधारी पहले ही बढ़ा दी है, जिससे प्राप्तियां बढ़ रही हैं।

प्रत्यक्ष कर संग्रह में आई ऐतिहासिक गिरावट

संशोधित अनुमान 11.7 लाख करोड़ रुपये प्रत्यक्ष कर संग्रह का था, जबकि 9.98 लाख करोड़ रुपये आए

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 1 अप्रैल

केंद्र सरकार ने 2019-20 में 9.98 लाख करोड़ रुपये कर संग्रह किया है। इसकी वजह से कर संग्रह के संशोधित अनुमान (आरई) की तुलना में 1.75 लाख करोड़ रुपये या 14.7 प्रतिशत की ऐतिहासिक कमी आई है। इस भारी अंतर के कारण वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग को वित्त वर्ष 2020-21 के बजट के पूरे गणित को बदलना पड़ सकता है।

राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कर विभाग के इतिहास में अब तक इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं आई। इसकी प्रमुख वजह व्यापक आर्थिक मंदी, बजट के बाद कॉर्पोरेट कर में कमी की घोषणा, कर समाधान योजना विवाद से विश्वास तक शुरू न हो पाना और सबसे ज्यादा कोरोनावायरस के चलते हुई देशबंदी है।

आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि प्रत्यक्ष कर के तहत 31 मार्च तक कुल सकल राशि (रिफंड जारी होने के पहले) 11.81 लाख करोड़ रुपये रही है। इसमें कर रिफंड करीब 183 लाख करोड़ रुपये है। कुल संग्रह से रिफंड के बाद शुद्ध कर संग्रह 11.7 लाख करोड़ रुपये पुनरीक्षित अनुमान की जगह 9.98 लाख करोड़ रुपये रहा है। इसमें से केंद्र सरकार को 5.42 लाख करोड़ रुपये कॉर्पोरेशन कर और 4.43 लाख करोड़ रुपये व्यक्तिगत आयकर मिले हैं। 9.98 लाख करोड़ रुपये की शेष राशि का संग्रह छोटे कर जैसे प्रतिभूति विनिमय कर (एसटीटी) से हुआ है। इस आंकड़े में कुछ सुधार भी हो सकता है क्योंकि कुछ बैंकों ने अभी संग्रह की प्राप्तियां नहीं दी हैं। बहरहाल उपरोक्त उल्लिखित अधिकारी ने कहा कि इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा।

वित्त वर्ष 20 के लिए प्रतिशत के हिसाब से आई गिरावट हाल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। यह 2018-19 में 5.3 प्रतिशत था। इसके पहले 2008-09 के संकट की स्थिति में यह संशोधित अनुमान का 7.5 प्रतिशत था।

केंद्रीय बजट 2020-21 में सरकार ने कर संग्रह का लक्ष्य घटाकर 11.70 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। पहले के अनुमान में 13.35 लाख करोड़ रुपये कर संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। सरकार ने कर संग्रह का लक्ष्य तार्किक बनाया था और 1.45 लाख करोड़ रुपये कॉर्पोरेशन कर की दरें घटाने से होने वाली कमी के अलावा कोई कमी नहीं की गई थी। इस कर में सबसे ज्यादा योगदान करने वाली देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, जहां से 37 प्रतिशत कर राजस्व आता है। मुंबई से कर संग्रह में संशोधित अनुमान की तुलना में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में मुंबई में कर संग्रह 3.09 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि 4.29 लाख करोड़ रुपये कर संग्रह का अनुमान लगाया गया था, जिससे कर संग्रह में 1.20 लाख करोड़ रुपये का भारी अंतर आया है। इसी तरह से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में कर संग्रह में 8 प्रतिशत की गिरावट आई है, और इसके बाद बेंगलूरु से कर संग्रह 5 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है।

सूत्रों ने कहा कि कर विभाग ने तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में अग्रिम कर भुगतान में आई गिरावट के बाद कवायद शुरू कर दी थी। तीसरी तिमाही में कॉर्पोरेशन कर संग्रह में पिछले साल की तुलना में 5 प्रतिशत गिरावट आई। जनवरी महीने में कुल संग्रह 7.3 लाख करोड़ रुपये रहा। चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में कंपनियों का अग्रिम कर भुगतान पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत गिर गया। एक सरकारी सूत्र ने कहा कि इस गिरावट से केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, जो चालू वित्त वर्ष में बढ़कर जीडीपी का 3.8 प्रतिशत हो गया है। फरवरी तक समग्र हिसाब से राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 20 के बजट लक्ष्य से 35 प्रतिशत ज्यादा हो गया है।

बहरहाल सरकार का ध्यान अभी आर्थिक स्थिति पर नहीं है और उसने वैश्विक महामारी कोविड-19 को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसकी वजह से हर आर्थिक गतिविधि पर लगाम लग गई है।

पिछले 5 साल में प्रत्यक्ष कर संग्रह (लाख करोड़ रु.)

वर्ष	संशोधित	वास्तविक
2015-16	7.52	7.42
2016-17	8.47	8.49
2017-18	10.05	10.02
2018-19	12.00	11.36
2019-20	11.7	9.98

स्रोतः आयकर विभाग, बजट दस्तावेज

विस्थापित श्रमिकों से अच्छे व्यवहार के निर्देश

सोमेश झा
नई दिल्ली, 1 अप्रैल

केंद्र सरकार ने बुधवार को देशबंदी से प्रभावित विस्थापितों के साथ सामाजिक मनोवैज्ञानिक मसलों पर व्यवहार को लेकर विस्तार से दिशानिर्देश जारी किए। सरकार ने राज्यों को अलग से परामर्श जारी कर इन कामगारों को एकांतवास में रखने की सलाह दी है।

सरकार ने राज्यों से कहा है कि हर विस्थापित मजदूर के साथ सम्मान, गरिमा, सहानुभूति और करुणापूर्ण व्यवहार किया जाए और उनकी समस्याओं को समझने के लिए उनकी बात को ध्यान से सुना जाए।

राज्यों को सलाह दी गई है कि वे मजदूरों को यह समझाएं कि देशबंदी की स्थिति क्षणिक है और यह लंबे समय तक नहीं रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के बाद यह दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

शीर्ष न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि देशबंदी की घोषणा होने के बाद करीब 6 लाख लोग अपने गृह राज्य के लिए पैदल निकल पड़े, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन और उद्योग में काम पर रोक लग गई थी।

दिशानिर्देश में कहा गया है, 'इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि वे जहां हैं, वहीं बने रहें और उन्हें बताया जाए कि अगर वे बड़े पैमाने पर विस्थापित होते हैं तो वायरस को रोकने की कवायद पर विपरीत असर पड़ेगा।'

सरकार के संज्ञान में यह आया है कि विस्थापितों को ऐसी स्थिति में सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक आघात से जूझना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें स्थानीय लोगों की उपेक्षा से जूझना पड़ सकता है और उन्हें अपने गृह जनपद में इंतजार कर रहे परिजनों की भी चिंता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, 'संचारी रोग कोविड-19 के हमले और नियमित गतिविधियों पर रोक के बाद विस्थापित मजदूर अपने गृह जनपद की ओर भागने लगे। तमाम मजदूरों ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हर तरह के तरीके अपनाए।'

इसमें कहा गया है कि तमाम विस्थापित मजदूर सीमाओं पर फंस गए और वे ज्यादातर समाज के हाशिये पर रहने वाले लोग हैं, जो रोजाना की कमाई पर निर्भर हैं और 'इस तरह की तनाव की स्थिति में उनके साथ सहानुभूति से पेश आने और समाज को इसे समझने की जरूरत है।'

सरकार ने पाया है कि उनकी तात्कालिक चिंता खाने, आवास, इलाज और संक्रमण फैलने, रोजगार छिन जाने, परिवार की चिंता और डर से जुड़ी हुई है। इसके अलावा उन्हें स्थानीय समुदाय से भी उपेक्षा मिल रही है। इसमें कहा गाय है कि यह सब देखते हुए उन्हें मजबूत सामाजिक संरक्षण की जरूरत है।

बुधवार को लखनऊ में सस्ते अनाज की दुकान पर राशन लेते लोग। कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशबंदी की गई है और राशन देने के दौरान एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की कवायद की जा रही है *-पीटीआई*

आखिरी तिमाही में घटीं परियोजनाएं

सचिन मामबटा
मुंबई, 1 अप्रैल

आर्थिक सुस्ती और कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ती अनिश्चितता के बीच वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में बहुत कम परियोजनाएं ही नजर आईं। नई परियोजनाओं की लागत मार्च 2020 में समाप्त हुई तीन महीने की अवधि में 7,000 करोड़ रुपये कम रही। यह जानकारी परियोजना ट्रेकर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से सामने आई है। नई परियोजनाओं का मूल्य मार्च 2019 में 2.98 लाख करोड़ रुपये थी जो मंगलवार को समाप्त तिमाही में घटकर 2.91 लाख करोड़ रुपये रह गई। मंगलवार को वित्त वर्ष 2020 का अंतिम दिन था। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में 71.3 फीसदी की कमी आई लेकिन अटकी परियोजनाओं के मूल्य में भी कमी आई है। अटकी परियोजनाओं के मूल्य में 82 फीसदी से अधिक की कमी हुई।

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि जून तिमाही के आंकड़ों से धारणा और अधिक स्पष्ट होगी जब कोरोना के भय से नई परियोजनाओं में भारी कमी आने के आसार हैं।

कोविड-19 नया वायरस है जिसके कारण बीमारी को फैलने से रोकने के लिए बंदी करने वाला चीन सबसे पहला देश है। उसके बाद कई देशों में बंदी की गई। इटली, फ्रांस और स्पेन में ऐसा किए जाने के बाद भारत ने भी 25 मार्च को देशबंदी की घोषणा की थी।

विश्लेषकों की राय में नई परियोजनाओं पर इसका दीर्घ अवधि का असर हो सकता है।

देशबंदी होने से आपूर्ति श्रृंखला और श्रमिकों की उपलब्धता बाधित है। कोरोनावायरस के मामले से पूंजीगत माल बनाने वाली कंपनियों की दो तिमाही का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है क्योंकि उनका राजस्व इन्हीं परियोजनाओं पर निर्भर करता है। यह जानकारी 31 मार्च को जारी की गई कैपिटल गुड्स रिपोर्ट से सामने आई है जिसे शोध विश्लेषकों चिराग शाह, अमित अनवानी और आदिल खान ने लिखा है।

ये सभी ब्रोकरेज कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की खुदरा विभाग आईसीआईसीआई डाइरेक्ट से जुड़े हैं।

रिपोर्ट कहती है, 'कोरोनावायरस के वास्तविक प्रसार का आकलन कर पाना कठिन है और फिलहाल तेल कीमत में गिरावट अभी भी चरम पर पहुंचना बाकी है। हालांकि, इससे घरेलू बाजार में तीन से छह महीने के राजस्व और लाभ से हाथ धोना पड़ सकता है जबकि यूरोप के देशों, अमेरिका, पश्चिम एशिया और चीन पर निर्भर या उनके साथ व्यापार करने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका लग सकता है। इन कंपनियों को निकट भविष्य में अनिश्चितता से उच्च जोखिम उठाना पड़ सकता है।' इसमें कहा गया है कि मार्च 2021 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2021) में इस क्षेत्र को ऑर्डर, क्रियान्वयन पर दबाव के साथ साथ कार्यशील पूंजी, नकद प्रवाह, बही खाता और लाभ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

विदेशी ब्रोकरेज कंपनी जेफरीज इंडिया की इक्विटी विश्लेषकों लाविना क्वाडरोस और अपूर्वा बहादुर ने अपने 30 मार्च की कंपनी अद्यतन रिपोर्ट में कहा कि निजी क्षेत्र की पूंजीगत माल की दिग्गज कंपनी लार्सन ऐंड टुब्रो को प्राइस/बुक (पीबी) मूल्यांकनों पर दबाव देखने को मिला है जो इससे पहले वैश्विक वित्तीय संकट के समय देखने को मिला था।

वैश्विक महामारी
कोरोनावायरस

नई परियोजनाओं की लागत मार्च 2020 में समाप्त हुई तीन महीने की अवधि में 7,000 करोड़ रुपये कम रही

बीएस सूडोकू 3704

			9		8		2	
9					3	5		
4	1			5	6		3	8
3						2		4
			8		2	3		5
		7		3			6	
1	5	3	6					
	7	6	2		5		9	
2	4			8	7			6

परिणाम संख्या 3703

3	2	1	8	9	7	5	4	6
8	5	9	4	6	1	3	2	7
4	7	6	2	3	5	8	9	1
9	1	3	7	8	6	2	5	4
2	6	7	5	4	3	9	1	8
5	8	4	1	2	9	6	7	3
6	3	2	9	1	4	7	8	5
7	4	8	6	5	2	1	3	9
1	9	5	3	7	8	4	6	2

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल
★★★★★

अमेरिका-यूरोप से ऑर्डर रद्द होने की निर्यातकों को आशंका

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 1 अप्रैल

फरवरी में निर्यात में अचानक से तेजी देखे जाने के बाद फिर से यह क्षेत्र संकुचन की दिशा में तेजी से बढ़ रह है। निर्यातकों को यह डर सता रहा है कि विदेशी मुद्रा की कमाई वाले क्षेत्र में बड़े ऑर्डर रद्द किए जा सकते हैं।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, 'हमें मार्च में निर्यात में संकुचन के आसार दिख रहे हैं और बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मांग में आई संचयी गिरावट का असर अप्रैल में नजर आएगा जिससे बड़े स्तर पर निर्यात में कमी आएगी।'

कोरोनावायरस की चपेट में बुरी तरह से फंसे अमेरिका और यूरोप के बड़े ग्राहकों की ओर से एक के बाद एक ऑर्डर रद्द किए जाने से इंजीनियरिंग सामान और कपड़ा जैसे क्षेत्र को भारी चोट पहुंच सकती है। भारत से होने वाला इंजीनियरिंग निर्यात का 40 फीसदी इन्हीं दो बाजारों में जाता है। दूसरी तरफ यूरोप में भारत के प्रमुख कपड़ा निर्यात गंतव्यों में सस्ते बांग्लादेशी और वियतनामी विकल्पों से इस क्षेत्र पर पहले से ही दबाव बना हुआ है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन ए शक्तिवेल ने कहा, 'इस उद्योग को बैंकों से तुरंत मंजूरी और पैकिंग क्रेडिट दिए जाने, निर्यात बिलों का देर से भुगतान और बिना किसी जमानत के अग्रिम सीमा को बढ़ाकर 25 फीसदी किए जाने की तुरंत आवश्यकता है।'

उन्होंने कहा कि इसके अलावा अग्रिम फॉरेक्स बुकिंग और ईएमआई को छह महीने तक स्थगित किए जाने पर किसी तरह का जुर्माना नहीं होना चाहिए।

छह महीने की सुस्ती के बाद फरवरी महीने में निर्यात को थोड़ी गति मिली थी। इससे शीघ्र ही कारोबार सुधरने की उम्मीद जगी थी। हालांकि नीति निर्माता अब तक इन बातों पर सहमत नहीं हैं। एक वरिष्ठ सरकारी व्यापार विशेषज्ञ ने कहा, 'गत महीने निर्यात में मामूली बढ़ोतरी हुई थी। इसके साथ ही तेल कीमतों में अचानक से तेजी आई थी जिससे भारत को रिफाइंड पेट्रोलियम की बिक्री करने पर ज्यादा रकम मिल रही थी।'

तेल की कीमतों में तेजी आने से भारत को 3.4 अरब डॉलर की कमाई हुई थी। फरवरी महीने में इसमें 10 फीसदी की उछाल रही, जबकि जनवरी में इसमें 7 फीसदी की कमी आई थी। लेकिन उसके बाद सऊदी अरब और रूस के बीच जबरदस्त कीमत युद्ध के कारण उनके यहां तेल के दाम घटकर 18 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत 26 डॉलर प्रति बैरल रही।

निर्यात को श्रमिकों की जबरदस्त कमी के कारण भी नुकसान हो रहा है। बड़ी संख्या में श्रमिकों के शहरी औद्योगिक क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र में पलायन कर जाने के करण भी निर्यात को झटका लग रहा है। भारतीय परिधान विनिर्माता संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'श्रमिकों की किल्लत लगातार इस वजह से बनी हुई है कि उन्हें लग रहा है कि बंदी में रोजी रोटी चलाना मुश्किल होगा।'

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 36

आईटी के लिए कठिन समय

कोरोनावायरस से उपजी महामारी के प्रसार ने वैश्विक मूल्य शृंखला पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। देश के सर्वाधिक एकीकृत क्षेत्र भी स्पष्ट जोखिम में नजर आ रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ा सेवा क्षेत्र (आईटीईएस) भी उनमें से एक है।

इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) जैसी अव्वल कंपनियां इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं। वैश्विक स्तर पर मांग में कमी आई है जो भविष्य में इन कंपनियों के ऑर्डर पर असर डालेगी।

वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने भी आईटीईएस की वृद्धि पर गहरा असर डाला था। संकट से पहले इस क्षेत्र का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। नोमुरा के एक विश्लेषक की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2007-08 में इसमें 30 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली थी। परंतु उसके बाद के दो वित्त वर्ष में वृद्धि में पहले 17 फीसदी और उसके बाद 6 फीसदी गिरावट आई। वैश्विक कंपनियों के व्यय में भारी कमी आई और इसने कंपनियों के राजस्व को प्रभावित किया।

यह देखना होगा कि मौजूदा संकट के कारण मांग में जो कमी आई है वह उसी स्तर की है या नहीं। आईटीईएस के ग्राहक आधार की बनावट को देखते हुए चिंतित होने की साफ वजह है। विश्लेषकों का मानना है कि इस समूचे क्षेत्र की राजस्व वृद्धि केवल 3 से 8 फीसदी के बीच रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में बैंकिंग ग्राहक शायद नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा परिचालन क्षेत्र की तमाम बड़ी बाधाएं भी मौजूद हैं। इन्फोसिस ने मीडिया से कहा है कि कंपनी के 2.40 लाख कर्मचारियों में से 70 फीसदी घर से काम कर रहे हैं। टीसीएस के कुल 4 लाख कर्मचारियों में से 40 फीसदी घर से काम कर रहे हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब खुद इनके ग्राहक भी अपने कामकाज और आईटी व्यवस्था की निरंतरता को लेकर चिंतित होंगे। आईटीईएस क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को भी कर्मचारियों के घर से काम करने के कारण कामकाज में कटौती करनी पड़ रही है।

सवाल यह है कि यह कठिन समय क्या केवल फौरी है। भारतीय आईटीईएस क्षेत्र वैश्विक वित्तीय संकट के बाद खराब दौर से गुजर चुका है और बड़ी बाजार हिस्सेदारी की तलाश में है।

इस क्षेत्र के ऊपर मौजूदा हालात का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा? यह मानने की पर्याप्त वजह है कि प्रभाव शायद सकारात्मक न हो। श्रम आधारित आईटीईएस कंपनियों पर संकट के इस समय में अपने कर्मचारियों को बनाए रखने का दबाव होगा। कॉग्निजैंट ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि वह अपने दो तिहाई भारतीय और फिलीपीनी कर्मचारियों को अप्रैल में 25 फीसदी बोनस देगी। अब इसकी समीक्षा होगी।

यह इस क्षेत्र के व्यापक रुझान में हस्तक्षेप है। यह क्षेत्र डिजिटल की ओर बढ़ेगा जहां शायद पहले की तरह कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रहेगी। अमेरिका के राजनीतिक हालात में विदेशी कामगारों के खिलाफ माहौल तैयार हो चुका है। इस बात ने भी आईटीईएस क्षेत्र के कारोबार को प्रभावित किया है। आईटीईएस क्षेत्र के मौजूदा तरीकों से संचालित होने वाली कंपनियों से दूरी बनाने का दबाव भविष्य में और बढ़ेगा। देश का आईटीईएस क्षेत्र सन 2000 के दशक में और 2008 के बाद दो बार यह साबित कर चुका है कि वह संकट से उबरकर नई ताकत के सामने आता है। यह अवसर सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देश की बड़ी कंपनियों को अपने कारोबारी मॉडल को नए सिरे से संवारना होगा। ऐसा करके ही वे राजस्व वृद्धि में सुधार कर पाएंगी।

अजय मोहंती

रक्षा कूटनीति की अपनी सीमाएं

भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि पिछले एक साल में बुरी तरह प्रभावित हुई है और उसने रक्षा को अपनी विदेश नीति की धुरी बना लिया है। लेकिन इस रणनीति के सीमित फायदे हैं। बता रहे हैं **प्रेमवीर दास**

यह देखना दिलचस्प है कि 'रक्षा कूटनीति' हमारी विदेश नीति की धुरी बन गई है। पिछले वर्षों में विदेश मंत्रालय ने शायद ही कभी राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने के लिए सैन्य वार्ताओं का सहारा लिया था। विदेश नीति में हमारा जोर आर्थिक मुद्दों, व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों आदि पर रहता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे तरकश में ये कूटनीतिक शस्त्र कम हो गए हैं। हाल की घटनाएं इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि रक्षा संबंध हमारी विदेश नीति की धुरी बन गए हैं।

मई 2019 में शानदार चुनावी जीत के बाद बनी नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के लिए सभी चीजें अनुकूल थीं। अर्थव्यवस्था में जरूर कुछ सुस्ती दिख रही थी लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी। जुलाई में पेश किए गए बजट की अधिकांश घोषणाओं को अगले दो-तीन महीनों में वापस लेना पड़ा। इसके साथ ही अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। हालांकि यह हमारे संप्रभु अधिकारों के दायरे में था लेकिन इससे एक सहिष्णु राज्य के रूप में हमारी विश्वसनीयता पर कुछ सवाल खड़े हुए। कुछ समय बाद भारत को दुनिया को यह समझाना पड़ा कि उसने घरेलू स्तर पर जो कदम उठाए हैं, वे सही हैं।

यह मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि नागरिकता संशोधन कानून ने जाने-अनजाने धर्म को एक बार फिर राज्य की नीति के केंद्र में ला दिया। इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और इस बार फिर सरकार को ज्यादा आक्रामकता के साथ अपना बचाव करना पड़ा। विदेश मंत्री को तो यहां तक कहना पड़ा कि 'अब हमें पता है कि कौन हमारा दोस्त है।' इससे कई देश भारत के दोस्तों की सूची से बाहर हो गए। इनमें ईरान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश शामिल हैं। इन देशों के अहम नेताओं ने भारत की घरेलू नीतियों की आलोचना करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। इनमें कुछ इस मामले में दूसरों से ज्यादा मुखर थे।

ऐसे माहौल में अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर डाली। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कई मंचों पर कहा कि भारत और पाकिस्तान सवाल के दो पहलू हैं। इससे पहले अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान ने सार्वजनिक तौर पर ऐसी बात कहने से परहेज किया था। इस समय अर्थव्यवस्था में भी गिरावट का दौर है, कई क्षेत्रों में संस्थागत खामियों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्थिति कमजोर हुई है। सच्चाई यह है कि भारत की साख एक साल पहले जैसी नहीं रही, बल्कि दूर-दूर तक वैसी नहीं है।

ऐसे चिंताजनक माहौल में, अगर किसी चीज ने भारत को कुछ हद तक संभाले रखा है तो वह है रक्षा कूटनीति। जैसे कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि पिछले 10 साल में यह स्थिति आई है। भारत ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा है और भारत के पोत दूसरे देशों के बंदरगाहों का दौरा कर रहे हैं। अधिकांश देशों के साथ इस तरह की कवायद का ज्यादा मतलब नहीं है लेकिन खासकर अमेरिका और जापान के साथ इस तरह के अभियान बेहद सफल रहे हैं।

भारत ने 2002 में अमेरिका से सैन्य साजोसामान की खरीद शुरू की थी और अब तक वह उससे 20 अरब डॉलर से अधिक की खरीद कर चुका है। इनमें मुख्यत: विमानों की खरीद शामिल हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच कुछ अहम रक्षा सौदे भी हुए हैं जिनके तहत प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी होना है। जापान अब समुद्र में होने वाले त्रिपक्षीय मालाबार अभ्यास का नियमित हिस्सा है।

कई बार यह दावा किया जा चुका है कि हिंद-प्रशांत परस्पर हित का मंच है लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि इस बारे में हमारी समझ अलग है। समुद्र में आवागमन की आजादी को अलग रख दें तो इसके उद्देश्य की कोई सटीक पहचान नहीं है। कूटनीतिज्ञों और रणनीतिकारों ने परोक्ष रूप से ऐसे संकेत दिए हैं कि इसका असली मकसद इस क्षेत्र के चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना है लेकिन यह संकेत नहीं देते हैं कि किसी तरह के सैन्य गठबंधन के बिना यह कैसे होगा और चीन कैसे हमारे कुछ साझा हितों के लिए खतरा है। अमेरिका की प्रशांत और मध्य कमान के जरिये हमेशा इस क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी रही है जबकि हमारे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की मानें तो हमारी आकांक्षा केवल प्रायद्वीपीय है।

इससे भारत हिंद-प्रशांत में एक अहम ताकत नहीं बनेगा। आम बजट में रक्षा के लिए महज 14 फीसदी राशि आवंटित की गई है। तीन दशक पहले भी यह राशि लगभग इतनी ही थी। भारत के जिन अन्य देशों के साथ सामुद्रिक रक्षा संबंध हैं, उनके लिए हिंद प्रशांत सहयोग का आधार नहीं है। इनमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शामिल हैं। रूस ने तो सार्वजनिक रूप से इस अवधारणा का मजाक उड़ाया था और वह भी विदेश मंत्रालय द्वारा भारत में आयोजित सम्मेलन में। इसलिए पिछले दशक में हमारी रक्षा कूटनीति का अहम हिस्सा अमेरिका के साथ संबंध रहे हैं। इन संबंधों की धुरी अमेरिका से सैन्य साजोसामान की खरीद है।

अगर रक्षा कूटनीति हमारी विदेश नीति का अहम हिस्सा बन गई है तो यह अच्छी बात है। ट्रंप के हालिया दौरे की एकमात्र उपलब्धि यह रही कि इस दौरान 3 अरब डॉलर के सैन्य हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए सौदा हुआ। ऐसी कोई वजह नहीं है कि इस तरह की वार्ता नहीं होनी चाहिए लेकिन इनकी अपनी सीमाएं हैं।

दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो हम पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। इनमें चीन और रूस प्रमुख हैं। चीन के साथ हमारी हजारों किलोमीटर लंबी विवादित सीमा है और दोनों देशों के सुरक्षा संबंधों में भी तनाव है। रूस से साथ हमारे छह दशक पुराने सैन्य संबंध हैं लेकिन अब उसमें कुछ दरारें आ गई है। मुस्लिम दुनिया में ईरान को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी तरह आसियान में इंडोनेशिया और पड़ोस में बांग्लादेश की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है।

विदेशों में भारत की छवि घरेलू मुद्दों से परिभाषित हो रही है। रक्षा कूटनीति अपने आप इस नकारात्मकता को दूर नहीं कर सकती है। दुर्भाग्य से इस महीने पूर्वी तट पर होने वाले 38 देशों के पोतों के अभ्यास को कोरोनावायरस के कारण रद्द कर दिया गया है। यह भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को सुधारने का बेहतरीन मौका था।

कुल मिलाकर भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभरना चाहता है तो उसे चमकता हुआ दिखना चाहिए, बिखरता हुआ नहीं। भारत को अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को ध्यान में रखते हुए अपने घरेलू मुद्दों को सुलझाना चाहिए। रक्षा कूटनीति हमें यहीं तक ला सकती है, इससे आगे नहीं।

(लेखक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं।)

वित्तीय आपातकाल लगाना हो सकता है उपयोगी

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

प्रशासन के कामकाज में सुधार की दिशा में काम कर रही संस्था सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी ऐंड सिस्टेमिक चेंज (सीएएससी) ने 26 मार्च को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की। इसमें मांग की गई है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र को वित्तीय आपातकाल घोषित करना चाहिए। यह जनहित याचिका है जिसमें उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों का इस्तेमाल करने का आदेश दे।

इससे दो दिन पहले यानी 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों और कंपनियों के लिए विभिन्न वैधानिक नियमों और प्रक्रियाओं के तहत समयसीमा आगे बढ़ाने के सरकार के फैसले के बारे में बताया था और उस दौरान वित्तीय आपातकाल लगाने की संभावना से इनकार किया था। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि कुछ रिपोर्टों में देश में वित्तीय आपातकाल लागू करने का दावा किया जा रहा है लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है।

हालांकि इस तरह की अटकलों का बाजार गर्म था कि नरेंद्र मोदी सरकार कोविड-19 के कारण पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय आपातकाल लागू करने पर विचार कर सकती है ताकि अर्थव्यवस्था को इसके प्रतिकूल असर से उबारने के लिए ज्यादा फंड दिया जा सके। वित्तीय आपातकाल को प्रोत्साहन पैकेज से भी जोड़कर देखा जा रहा था। पिछले कई दिनों में कई सरकारों ने इसी तरह के उपाय किए हैं और माना जा रहा है कि मोदी सरकार भी इसकी घोषणा कर सकती है।

देश को सीएएससी द्वारा दायर जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय की प्रतिक्रिया का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा जिसमें देश में वित्तीय आपातकाल लगाने की मांग की गई है।

वित्तीय आपातकाल में क्या होता है?

भारतीय संविधान में तीन तरह के आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के तहत अगर सरकार को लगता है कि युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश या उसके किसी भूभाग की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है तो वह राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है। इस तरह के आपातकाल में केंद्र सरकार सभी तरह की कार्यकारी, विधायी और वित्तीय शक्तियां अपने हाथ में ले लेती है और राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है।

इस दौरान अनुच्छेद 20 (अपराधों की सजा के खिलाफ संरक्षण का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित रहते हैं। देश में अब तक तीन बार इस तरह का आपातकाल लागू किया गया है। 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था।

दूसरी तरह का आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में लागू किया जा सकता है। इसके तहत अगर किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी नाकाम हो जाती है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पिछले कई वर्षों के दौरान कई राज्यों में इसका इस्तेमाल किया गया है। राज्य में निर्वाचित सरकार के गठन के साथ ही इसे हटा दिया जाता है।

अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा है तो वह अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। इस तरह के फैसले को संसद को दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए और उन्हें दो महीने के भीतर एक प्रस्ताव पारित इसे मंजूरी देनी होगी। इसके प्रावधानों के तहत केंद्र खुद पर और सभी राज्य सरकारों पर वित्तीय स्वामित्व के मानक लागू कर सकता है। इसके लिए राज्यों के बजट भी केंद्र को ही पारित करने होंगे। अब तक किसी भी सरकार ने देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया है।

अनुच्छेद 360 के तहत सबसे अहम अधिकार यह है कि केंद्र अपने और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी कर सकता है। इनमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल हैं। यह ऐसा प्रावधान है जो जरूरत पड़ने पर केंद्र को वित्तीय मोर्चे पर भारी राहत दे सकता है। सभी राज्यों का कुल व्यय में वेतन और भत्तों का हिस्सा करीब 25 फीसदी है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए यह राशि 9 लाख करोड़ रुपये होगी। केंद्र के असैन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का खर्च करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये है।

इस तरह वित्तीय आपातकाल से केंद्र को अपने और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती की छूट मिलेगी जो कुल मिलाकर करीब 11.5 लाख करोड़ रुपये है। उनके वेतन में 10 फीसदी कटौती से केंद्र को करीब 1.15 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।

लेकिन यह एक मुश्किल फैसला होगा जिससे सरकार की लोकप्रियता बुरी तरह प्रभावित होगी। कोई भी सरकारी कर्मचारी वेतन में कटौती नहीं चाहेगा और हर कोई इस दर्द को लंबे समय तक याद रखेगा। लेकिन ऐसे समय, जब कई निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को छोड़ रही है, अपने कारोबार को बंद कर रहीं हैं जिससे लोग बेरोजगार हो रहे हैं और यहां तक कि वेतन में भी कटौती की जा रही है, वित्तीय आपातकाल में वेतन कटौती का प्रावधान एक विकल्प है जिस पर सरकार विचार कर सकती है।

देश को सीएएससी द्वारा दायर जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय की प्रतिक्रिया का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा जिसमें देश में वित्तीय आपातकाल लगाने की मांग की गई है।

कानाफूसी

गरीब कल्याण की कवायद

कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णायक संस्था यानी कांग्रेस कार्य समिति ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बैठक का आयोजन किया। कांग्रेस ने अपनी राज्य सरकारों से कहा है कि वे उन गरीबों की मदद के लिए तत्पर रहें जो कोविड-19 के कारण चल रहे 21 दिन लंबे लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। पार्टी इस विषय पर गुरुवार को अपनी योजना पेश करेगी। पार्टी का विचार यह है कि ऐसा करके वह देश के गरीबों को यह अहसास करा सकती है कि पार्टी मुसीबत में उनके साथ खड़ी है। दरअसल सन 2015 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यानी भाजपा की सरकार को गरीब कल्याण की सरकार बता रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि लॉकडाउन के कारण मची अफरातफरी में जब लाखों लोग यहां-वहां विस्थापित हो रहे हैं, पार्टी के पास अवसर है कि वह गरीबों के बीच अपनी जगह मजबूत कर सके।

निधि पर दुविधा

उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू तथा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपनी-अपनी सांसद विकास निधि में से एक-एक करोड़ रुपये की राशि कोरोनावायरस से निपटने के लिए बने केंद्रीय फंड में दें। परंतु मंगलवार को राज्य सभा के सचिव पीपीके रामाचारयुलु ने बताया कि 30 मार्च तक केवल 250 सांसदों ने ही ऐसा करने की सहमति दी थी। दोनों सदनों में मिलाकर 780 से अधिक सांसद हैं। इनमें से कई विपक्षी सांसद यह राशि या तो अपनी पार्टी के शासन वाली राज्य सरकार को देना चाहते हैं या फिर वे सीधे अपने राज्य या क्षेत्र के अस्पतालों को यह राशि देना चाहते हैं। केवल विपक्षी ही नहीं बल्कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों को भी अभी केंद्रीय पूल में यह राशि जमा करनी है। उनका कहना है कि उनके क्षेत्रों से दबाव आ रहा है कि वे अपने क्षेत्रों के अस्पतालों में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएं।

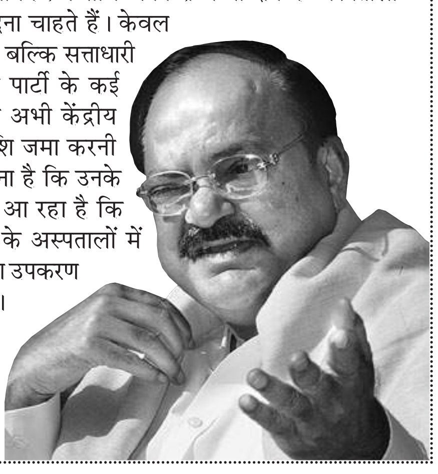

आपका पक्ष

लॉकडाउन में मजदूरों की लाचारी झलकी

लॉकडाउन के बाद दिल्ली के आनंद विहार में उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों के मजदूरों का अपने घर जाने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा था। लॉकडाउन का विरोध कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन जो लोग आजीविका के लिए घरों से बाहर थे वे अब अपने घरों में सुरक्षित होना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने कई तरह के इंतजाम किए हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि अपने घर में ही सुरक्षित रह सकते हैं। आजादी के बाद शायद ही कभी किसी को ऐसा दृश्य देखने को मिला हो कि लोग अपने सिर पर सामान और बच्चे, पत्नी को लेकर पैदल ही घर के लिए निकल पड़े। मजदूर मजबूर हैं न कि विरोध में ऐसा कर रहे हैं। मजदूरों का सैकड़ों किलोमीटर चलना उनके साहस को दिखाता है। भविष्य में जब भी स्थिति सामान्य होगी तो क्या ऐसे मजदूर दोबारा वापस काम के लिए अपने घरों से इतनी दूर जाएंगे।

हर्षवर्धन सिंह चौहान, रायबरेली

पूरे देश में लॉकडाउन के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर पैदल घर लौटने लगे थे

कोरोना संक्रमण से सबक लेना जरूरी

आज दुनिया के कई देश कोरोना के संक्रमण से ग्रस्त हैं। इटली, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका में तेजी कोरोना फैला है। कोरोना संक्रमित देशों की इस महामारी से निपटने के लिए पूर्व तैयारी नहीं थी और स्थिति समझने में भी लापरवाही बरती गई। इसके पहले वर्ष 2014 में इबोला वायरस के संक्रमण से पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी, सियेरा लियोन और नाइजीरिया में हजारों लोगों की मौत हुई थी। विकसित देशों का हमेशा से प्रगतिशील देशों को सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये के हथियार बेचने पर जोर रहा है। भविष्य में सभी देशों को एकजुटता होकर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर देना होगा। अगर भविष्य में कोई देश किसी वायरस से संक्रमित होता है तो वह देश गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था के दम पर उसे नियंत्रित कर सके।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

कई क्षेत्रों में एक साथ सुधार की जरूरत

भारत सहित दुनिया के कई देशों में आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। आर्थिक विकास दर का लगातार गिरना, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, बचत और निवेश में कमी, शेयर बाजार में गिरावट, तरलता का अभाव ऐसे आर्थिक संकेतक हैं जो इंगित करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक है। अर्थव्यवस्था की मजबूती को तीन क्षेत्रों की उत्पादक गतिविधियां तय करती है जिसमें विनिर्माण, सेवा और कृषि हैं। वर्तमान में तीनों क्षेत्रों के प्रदर्शन से ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्था देश में मंदी के दौर से गुजर रही है। इसलिए नौकरियां देने वाले क्षेत्रों मसलन कपड़ा, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियायती आवास को मजबूत करना होगा। इसके लिए आसान कर्ज मुहैया कराना होगा। जीएसटी को तर्कसंगत करने साथ ग्रामीण खपत बढ़ाने, ग्रामीण जनसंख्या की क्रय शक्ति में वृद्धि और कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। पूंजी निर्माण के लिए बचत-निवेश अनुपात में वृद्धि कर कर्ज की कमी दूर करनी होगी। हमें अमेरिका-चीन में चल रहे ट्रेडवॉर के चलते खुल रहे नए निर्यात बाजारों को पहचानना होगा तथा घरेलू उद्यमों को पुनर्जीवित करना होगा। तभी हम 3 से 4 साल में उच्च विकास दर को वापस पा सकते हैं।

डॉ. महेश बंसिया, उज्जैन

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

कहीं मंडियां खुलीं तो कहीं मुश्किलें

देश के कई राज्यों में खाद्य सामग्री और सब्जियों की आवक धीरे-धीरे सामान्य हो रही है

बीएस संवाददाता

देशव्यापी लॉकडाउन के एक सप्ताह बाद देश के बहुत से हिस्सों में कृषि मंडियां फिर चालू हो रही हैं। लेकिन ऐसा धीरे-धीरे हो रहा है और कुछ मंडियों में कारोबार अब भी पटरी पर नहीं आया है। ज्यादातर मंडियां कामगारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के इंतजाम कर रही हैं। बहुत सी मंडियों में आवक और आपूर्ति को नियंत्रित किया जा रहा है ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके।

कई इलाकों से खबरें आ रही हैं कि किसानों को सब्जियां मंडी में न पहुंचने के कारण फेंकनी पड़ रही हैं या पशुओं को खिलानी पड़ रही हैं। गुजरात के हालात चिंताजनक हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तिलहन की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ऐसे में तेल पेराई इकाइयां कह रही हैं कि उन्हें किसानों से सीधे खरीद की मंजूरी दी जाए।

वाशी सब्जी मंडी चालू है, लेकिन यहां भीड़ को दूर रखने के लिए एक व्यवस्था अपनाई गई है। मंडी में सब्जियों के आने और जाने का अलग-अलग समय तय किया गया है। अनाज मंडी में भी भीड़ घटाकर 20 फीसदी कर दी गई है।

वाशी मंडी के निदेशक सुशील सिंगाटकर ने कहा, 'कम से कम 1,500 लोग रोजाना मंडी में आते हैं, जिन्हें संभालना मुश्किल है। इसलिए हमने प्रवेश की एक निश्चित सीमा तय करने का फैसला लिया है।' वर्धा मंडी शुक्रवार को अनाज का कारोबार खोलने की योजना बना रही है। यह मंडी किसानों, कारोबारियों, मथाड़ियों (कामगारों) और आढ़तियों के लिए खुली है, लेकिन आवक बहुत कम बनी हुई है।

वर्धा मंडी के चेयरमैन श्याम भीमरावजी कार्लेकर ने कहा, 'सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए हम एक समय 10 किसानों के बिक्री ऑर्डर स्वीकार कर रहे हैं और बिक्री नीलामी में 10 खरीदारों को शामिल होने की मंजूरी दे रहे हैं।' महाराष्ट्र में प्याज मंडी लासलगांव पहले त्योहार की वजह से और बाद में पास के गांव में कोरोनावायरस का एक मरीज मिलने से बंद है। किसानों को अपना प्याज अन्य मंडियों में बेचना पड़ रहा है।

पटना में मंडी से अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी करते लोग फोटो-पीटीआई

- मंडियों में भीड़ से बचने के लिए आवक और आपूर्ति को किया जा रहा है नियंत्रित
- बिहार में किसानों के सब्जियों को फेंकने या पशुओं को खिलाने की आ रही खबरें
- मध्य प्रदेश, राजस्थान में तिलहन की आपूर्ति हो रही प्रभावित
- महाराष्ट्र में प्याज मंडी लासलगांव पहले त्योहार और फिर पास के एक गांव में कोरोना का मामला आने से है बंद
- गुजरात में अनाज, दलहन और तिलहन की आवक पर पड़ रहा ज्यादा असर

गुजरात

गुजरात में ताजा सब्जियों और फलों पर तुलनात्मक रूप से कम असर पड़ा है, जबकि अनाज, दलहन और तिलहन पर ज्यादा असर पड़ा है। सौराष्ट्र की बड़ी मंडियों में किसान सब्जियां बेचने आ रहे हैं, लेकिन कारोबार बमुश्किल ही नजर आते हैं। अहमदाबाद कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के सचिव दीपक पटेल ने कहा, 'रोजाना आवक हो रही है, जिस पर मामूली असर पड़ा है। उदाहरण के लिए पहले ताजा सब्जियों की दैनिक आवक 17,000 क्विंटल थी, जो अब घटकर 15,000 क्विंटल पर आ गई है।'

हालांकि अनाज और दलहन की आवक पर कुछ असर पड़ा है क्योंकि स्टॉक घट रहा है और नई आवक को बाजारों में पहुंचने में कुछ समय लग रहा है।

ऑल गुजरात रोलर फ्लोर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सराफ ने कहा, 'मंडी में अनाज और दलहन की नीलामी बंद है। खेतों में फसल तैयार है, लेकिन मजदूर उपलब्ध नहीं हैं। आपूर्ति शृंखला भी प्रभावित हुई है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से परिवहन धीमा चल रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से कुछ आपूर्ति हो रही थी, जो अंतरराज्यीय लॉकडाउन की वजह से रुक गई है। हालांकि अभी तक कोई किल्लत नहीं है। उदाहरण के लिए गेहूं सरकार के एफसीआई गोदामों में उपलब्ध है। लेकिन निजी गोदाम खाली हैं क्योंकि नई आवक शुरू नहीं हुई है।'

दूसरी तरफ सौराष्ट्र क्षेत्र में राजकोट जैसे शहरों में 15 किलोग्राम के मूंगफली तेल के टिन के दाम बढ़कर 2,270 रुपये हो गए हैं। मंडी के सूत्रों के मुताबिक इस समय तेल पेराई लगभग बंद है और मंडी भी बंद है, जिससे मूंगफली की आवक थम गई है। सरकारी एजेंसी नैफेड ने नीलामी बंद कर दी है और इस समय उसके पास 6 लाख टन मूंगफली का स्टॉक है।

बिहार

बिहार में किसान एक अलग तरह के संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य में उपज और मांग है, लेकिन कई अवरोधों की वजह से वितरण के प्रबंधन के लिए कोई केंद्रीकृत स्थान नहीं है। कई जगह किसान सब्जियां फेंक रहे हैं या उसका इस्तेमाल पशुओं को खिलाने में कर रहे हैं। गेहूं की खरीद में देरी हो रही है। मिल गेहूं नहीं खरीद पा रही हैं और आटे की आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं। इससे खुदरा बाजार में आटे की किल्लत पैदा हो रही है, जिससे कीमतें भी बढ़ रही हैं। अब सरकार ने हालात को सामान्य करने के लिए दखल दिया है।

उत्तर भारत

लॉकडाउन से राष्ट्रीय राजधानी में एशिया की सबसे बड़ी कृषि मंडी आजादपुर से फल एवं सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों ने कृषि एवं बागवानी उपजों की दिल्ली के भीतर और अंतरराज्यीय आवाजाही को सामान्य बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। यहां आसपास के इलाकों से फल-सब्जियों की आवक हो रही है, लेकिन दूर के इलाकों से आवक प्रभावित हुई है।

आजादपुर मंडी में चावला फ्रेश वेजिटेबल्स के रोहित चावला ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'आजादपुर मंडी में कारोबार आधा हो गया है। हमारा ज्यादातर माल महाराष्ट्र से आता है लेकिन पिछले एक सप्ताह के दौरान राज्य से आने वाले ट्रकों की संख्या में भारी गिरावट आई है क्योंकि उनके चलने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।' हालांकि पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा की कृषि मंडियों में हालात कमोबेश समान हैं। आजादपुर में ज्ञानचंद ऐंड संस के ज्ञानचंद ने कहा, 'उत्तर प्रदेश से कृषि उपजों की आवक कम हुई है, जबकि मांग पहले ही कम हो चुकी है।'

पश्चिम बंगाल

पूर्वी भारत के सबसे बड़े जिंस बाजारों में से एक कोलकाता के पोस्ता बाजार में दुकानें मंडी की योजना के अनुसार बारी-बारी से खुल रही हैं। यहां राज्य के बाहर से अनाज, दलहन और अन्य आवश्यक खाद्य उत्पादों की ताजा आपूर्ति नहीं हो रही है। लेकिन पोस्ता बाजार मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चंदन चक्रवर्ती ने कहा कि बाजार में अगले 15 दिन की मांग पूरी करने लायक स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की उपलब्धता बड़ी समस्या है। यहां आलू और सब्जियों की आपूर्ति पर कम असर पड़ा है क्योंकि वे राज्य के विभिन्न जिलों से ट्रकों में आ रही हैं।

सड़कों पर ट्रकों की कमी से आपूर्ति में बढ़ी दिक्कत

शैली सेठ मोहिले

नवी मुंबई में एक सुपरमार्केट के मालिक महेंद्र चौधरी को साबुन, तेल और शैम्पू सहित आटा, चावल, और दाल जैसे अनाज की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। देशव्यापी बंदी की वजह से ऐसी चीजें लोग जरूरतमंदों के बीच बांट रहे हैं और दानदाताओं की तरफ से ऐसे सामानों की मांग बढ़ने की वजह से इनमें कमी दिख रही है। चौधरी ने कहा, 'सोमवार को किसी ने आटे के 50 पैकेट के साथ अन्य उपभोक्त वस्तुओं की मांग भी की थी जिसकी वजह से मेरे पास सामान खत्म हो गया।' चौधरी के सामने जो समस्या खड़ी हुई थी उसकी वजह से कारखानों और वितरण केंद्रों का बंद होना और सड़कों पर ट्रकों का प्रतिबंधित तादाद में चलना है।

पुलिस द्वारा परेशान किए जाने की आशंका और अज्ञात डर की वजह से भी बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवरों ने परिवहन केंद्रों पर अपने वाहन छोड़कर घर चले गए हैं। माल को बिना किसी बाधा के दूसरी जगह भेजने के लिए 21 दिन की देशबंदी के पहले सप्ताह में ही सरकार ने कई कदम उठाए लेकिन इसके बावजूद जमीन स्तर पर हालात कुछ और ही बयां करते हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि माल वाले परिवहन बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं क्योंकि विभिन्न हितधारकों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है और सड़क परिवहन को नीति निर्माताओं और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच पर्याप्त संपर्क न होने का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च ऐंड ट्रेनिंग (आईएफटीआरटी) के अनुसार, 50 लाख ट्रकों में से करीब 25 लाख ट्रक सड़क पर नहीं है।

कई जगहों पर फंसे ट्रक

आईएफटीआरटी के सीनियर फेलो एस पी सिंह ने कहा, 'सरकार ने लॉजिस्टिक्स से जुड़ी एक समिति का गठन किया है और यह आवश्यक सामानों की सुचारु आवाजाही के संबंध में बड़ा दावा कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि लॉकडाउन की वजह से सड़क परिवहन क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित हुआ है।' उन्होंने कहा कि इस बात पर भी कोई स्पष्टता नहीं है कि रबी की बंपर फसल की खरीद और वितरण को किस तरह से संभाला जाएगा। सिंह ने कहा कि सरकार ने गैर-जरूरी वस्तुओं की आवाजाही की अनुमति दी है लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि कारखाने, गोदाम आदि बंद है।

उन्होंने कहा कि ट्रकों की आवाजाही को सुचारु बनाने के लिए हाल की सभी पहल का कोई मतलब नहीं है जब तक कि पूरा तंत्र सामान्य तौर पर काम न करने लगे जिसमें ढाबा, भोजनालय, टायर मरम्मत की दुकान शामिल हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन बालमलकित सिंह ने कहा, 'ट्रक ड्राइवरों को डर है कि गाड़ी खराब होने की स्थिति में वे कई दिनों तक भोजन और पानी के बिना फंसे रहेंगे। इसलिए वे गांव चले गए हैं।'

एक ट्रक एग्रीगेटर मैवइन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी सचिन हरिताश का कहना है कि उसके प्रमुख ग्राहकों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, एमेजॉन, ग्रोफर्स और फ्लिपकार्ट शामिल हैं लेकिन कंपनी अपने ग्राहकों के लिए ट्रक पाने के लिए जूझ रही है। मैवइन के प्लेटफॉर्म पर 7,000 ट्रक पंजीकृत हैं जिनमें से केवल 4,000 ही चल रहे हैं। बाकी ट्रक ड्राइवर न होने की वजह से सड़क से दूर हैं। ये सभी ड्राइवर ट्रक के मालिक भी हैं।

पृष्ठ 1 का शेष

इलाज के लिए तैयार बड़े अस्पताल

फोर्टिस ने अपने कीमोथेरेपी डे केयर वार्ड को मुख्य आइसोलेशन वार्ड में बदला है। इसमें एक अलग प्रवेश द्वार है और साथ ही भोजन और बेवरिजेस सर्विस के लिए एक छोटी खिड़की भी है। पहले इसमें कैंसर के मरीजों को रखा जाता था। एएमआरआई के ढकूरिया यूनिट में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में चार बिस्तरों का एक वार्ड है और कोविड के संदिग्ध मरीजों के लिए एक अलग कमरा है। यहां आपातकालीन विभाग के प्रमुख और नोडल अधिकारी अशोक मिश्रा ने कहा कि इस वार्ड में तीन डॉक्टर और छह नर्स हैं।

हालांकि कोविड-19 के पॉजिटव या गंभीर मरीजों को आईटीयू में रखा जाता है जहां आइसोलेशन में दो बिस्तर हैं। विशेष रूप से कोविड-19 मरीजों के लिए बनाए आईटीयू में जाने का रास्ता अलग है। एएमआरआई में एक एक्स्ट्राकॉरपोरियल मेंबरेन ऑक्सीजिनेशन (ईसीएमओ) मशीन है जो सांस लेने में गंभीर समस्या आने पर मरीज को सहारा दे सकती है। ऐसी ही एक मशीन भुवनेश्वर यूनिट में भी है। इसका एक दिन के खर्च डेढ़ लाख रुपये है और तीन से पांच दिन तक मरीज को इसमें रखने पर साढ़े चार लाख रुपये खर्च हो सकते हैं। एएमआरआई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के मुख्य कार्यकारी और निदेशक रूपक बरुआ ने कहा कि अभी इसकी कीमत अहम नहीं है। उन्होंने कहा कि एएमआरआई कोविड के मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है।

गैर जरूरी माल गोदाम के बाहर

अदिति दिवेकर

देश में मौजूदा हालात के बीच वेयरहाउसिंग उद्योग, गोदाम परिचालन एवं भंडारण उद्योग को कारोबारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। माल वहन एवं भंडारण आदि से जुड़े कार्य प्रभावित होने से बंदरगाहों पर काफी माल जमा हो गया है। माव्यन के संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी परिचालन हरिताश ने कहा, देश के पूर्वी हिस्से में माल उतारने या भंडारण के लिए स्थानीय अधिकारियों से अनुमति मिलने में देरी हो रही है। अर्जी दिए 8 से 10 दिन हो गए हैं। अमूमन 1 से 2 दिनों में अनुमति मिल जाती है।

देश में लंबी दूरी तक माल का परिवहन करने वाली कंपनियों का कहना है कि उनके ट्रक चालक पिछले एक सप्ताह से माल नहीं उतार पा रहे हैं। हरिताश ने कहा, गोदामों में आवश्यक एवं गैर-आवश्यक दोनों वस्तुएं रखी जाती हैं। चूंकि, इस समय आवश्यक वस्तुओं की ही अनुमति दी जा रही है, इसलिए हमारे ट्रक दूसरे माल नहीं उतार पा रहे हैं।

माव्यन के 7,000 ट्रक हैं, लेकिन केवल 4,000 ट्रक ही इस समय चल रहे हैं। इनके जरिये मोटे तौर पर अभी किराना सामान, आवश्यक विनिर्माण वस्तुओं एवं दवा उत्पादों का ही परिवहन हो रहा है।

भंडारण कार्य प्रभावित होने से बंदरगाहों पर काफी माल जमा हो गए

हालांकि देश के उत्तरी भाग में गोदामों का परिचालन अच्छी तरह हो रहा है। दिल्ली स्थित एस एम लॉजिस्टिक ऐंड वेयरहाउसिंग के परिचालन प्रबंधक संजय सिंह यादव ने कहा, 'एफएमसीजी कंपनियों ने गोदामों के लिए आवश्यक अनुमति दिलाने में मदद की है। वाहन पंजीकृत कराने में भी इन कंपनियों की मदद मिली है। हालांकि कर्मचारियों की कमी से काम तेजी से नहीं हो रहा है।'

कंपनी के पास आवश्यक एवं गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए अलग गोदामों की व्यवस्था है। फिलहाल गैर-आवश्यक वस्तुओं के गोदाम बंद हैं। यादव ने कहा, 'हमें कम कर्मचारियों के साथ काम करना पड़ रहा है। हम केवल जरूरी भर कर्मचारियों को बुला रहे हैं और वे प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम कर रहे हैं। एसएम लॉजिस्टिक इस समय आवश्यक वस्तुओं जैसे शिशुओं के भोजन, नमक, खाद्य तेल, तैयार खाना, पोषक तत्त्व तथा कुछ दूसरे सामान ही गोदामों में रख रही है। कंपनी के गोदामों में मैरिको, अदाणी, नेस्ले के उत्पाद हैं।'

उद्योग के लोगों का कहना है कि दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में भी आवश्यक वस्तुओं के गोदाम खुले हैं, लेकिन मजदूरों की कमी है। चेन्नई के कई इलाकों में मजदूर नहीं मिलने से वस्तुओं का भंडारण नहीं हो रहा है।

ई-कॉमर्स में डिलिवरी बॉय की कमी

फ्लिपकार्ट लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए रेलवे और डाक विभाग जैसे संगठनों के साथ गठजोड़ की तलाश में

लॉकडाउन के बाद डिलिवरी बॉय अपनी सुरक्षा के डर से नहीं आ रहे

पीरजादा अबरार और समरीन अहमद

एमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बिगबास्केट जैसी विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियां कह रही हैं कि वे अपनी सेवाएं बहाल कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सी कंपनियों को उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की डिलिवरी में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इन्हें कर्फ्यू पास और डिलिवरी कर्मचारियों की कमी से जूझना पड़ रहा है। सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 महामारी का प्रसार रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन सख्ती बरत रहा है, इसलिए डिलिवरी बॉय अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं।

देश में एक सामुदायिक और उपभोक्ता प्लेटफॉर्म लोकलसर्कल्स के संस्थापक और चेयरमैन सचिन तापड़िया ने कहा, 'ज्यादातर स्थानीय अधिकारी लॉकडाउन के नियमों को कड़ाई से लागू कर रहे हैं। इससे डिलिवरी बॉय अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं और वे अपने काम पर नहीं आ रहे हैं। इन डिलिवरी बॉय में से बहुत से प्रवासी हैं, जिनमें से बहुत से वापस अपने घर चले गए हैं। ऐसे में उन्हें वापस लाना बड़ी चुनौती होगी।' लोकलसर्कल्स विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करता है।

तापड़िया ने कहा कि देश के विभिन्न जिलों में बहुत से डिलिवरी बॉय को कर्फ्यू पास नहीं मिले हैं। इनका मिलना आसान नहीं है और इन्हें जारी करने की मैनुअल प्रक्रिया के कारण इनमें कई दिन लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को कर्फ्यू पास के बजाय एक वैध पहचान-पत्र और ई-कॉमर्स कंपनी का लैटर स्वीकार करना चाहिए।

> शृंखला और डिलिवरी कर्मचारियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि ग्राहकों को उत्पादों की डिलिवरी के लिए क्षमता बढ़ाई जा सके

तापड़िया ने कहा, 'इसके अलावा कई गांवों में ई-कॉमर्स कंपनियों के बड़े गोदाम हैं। इन गांवों के सरपंच ई-कॉमर्स कंपनियों के डिलिवरी बॉय को गांव में आने-जाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए ई-कॉमर्स कंपनियां देश भर से प्राप्त ऑर्डरों में से आधे से भी कम की डिलिवरी कर पाई हैं। संसाधनों और डिलिवरी बॉय के उपलब्ध न होने के कारण बड़ी तादाद में ऑर्डर लंबित पड़े हैं।' इन ई-कॉमर्स कंपनियों में से कुछ को डिलिवरी के लिए सभी मंजूरियां मिली हुई हैं, लेकिन उनके पास डिलिवरी बॉय की किल्लत है। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन (आईएसएफ) की अध्यक्ष ऋतुपर्णा चक्रवर्ती ने कहा, 'ई-कॉमर्स क्षेत्र के मौजूदा हालातों के लिए नियोक्ता जिम्मेदार नहीं हैं। लॉकडाउन की घोषणा से दूसरे शहरों और कस्बों के कर्मचारी बोरियां-बिस्तर समेटकर अपने घर वापस चले गए।'

चक्रवर्ती ने कहा, 'ये ई-कॉमर्स कंपनियां आवश्यक सेवाएं मुहैया कराकर अपना परिचालन जारी रख सकती थीं, लेकिन उनके पास डिलिवरी के लिए कर्मचारी नहीं हैं। हालांकि मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है।'

ईवाई इंडिया में पार्टनर और नैशनल लीडर (ई-कॉमर्स एवं उपभोक्ता इंटरनेट) अंकुर पाहवा ने कहा कि केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स के लिए कुछ एकसमान नियम तय किए हैं, लेकिन राज्यों, शहरों और जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन अलग-अलग नियमों का पालन कर रहा है। उन्होंने कहा, 'गोदामों में कर्मचारियों की कमी से भी उत्पादों को पैक और डिलिवर करने के काम में अड़चन आ रही है। वहीं बहुत से डिलिवरी बॉय अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं, इसलिए वे अपने राज्यों में वापस लौट गए हैं। बहुत से लोग रोजगार बाजार से बाहर हो गए हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़ी तादाद में ऑर्डर मिल रहे हैं। लोग खरीदारी के लिए बड़ी तादाद में डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश डिलिवरी का पर्याप्त बुनियादी ढांचा ही मौजूद नहीं है।' विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों के अधिकारियों ने नाम प्रकाशित नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार और पुलिस समेत स्थानीय सार्वजनिक सेवा एजेंसियों को देश भर में ई-कॉमर्स उद्योग में कार्यरत लाखों डिलिवरी बॉय का भरोसा जीतने और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देने की तत्काल आवश्यकता है। एक ई-कॉमर्स कंपनी के अधिकारी ने कहा, 'डिलिवरी बॉय उपलब्ध नहीं हैं। उनकी उपस्थिति बहुत कम है।'

फ्लिपकार्ट लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए रेलवे और डाक विभाग जैसे संगठनों के साथ गठजोड़ की संभावनाएं तलाश रही है। फ्लिपकार्ट में चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार ने कहा, 'देश भर में हमारे विक्रेताओं और वेंडरों से ग्राहकों तक आवश्यक आपूर्ति पहुंचाने के लिए हमारी टीम रेलवे सहित गठजोड़ की सभी संभावनाओं पर विचार कर रही है। इन सभी विचारों और सरकार के सहयोग से हमें बहुत जल्द आवश्यक वस्तुओं की डिलिवरी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।' उन्होंने कहा, 'हम भर्तियां कर रहे हैं और किराना और आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी आपूर्ति शृंखला और डिलिवरी कर्मचारियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि ग्राहकों को उत्पादों की डिलिवरी के लिए क्षमता बढ़ाई जा सके।'

हालांकि ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन ने कहा कि वह धीरे-धीरे सेवाओं को बहाल कर रही है। लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर चावल या चाय जैसी आवश्यक वस्तु का ऑर्डर देते हैं तो यह ऐप दिखाता है कि बेंगलूरु जैसी जगह पर इसकी डिलिवरी कम से कम एक महीने में होगी, जो कंपनी का मुख्यालय है। एमेजॉन के प्रवक्ता ने कहा, 'हम धीरे-धीरे सेवाएं बहाल कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से मंजूरी और पास मिलने के बाद शहरों में सेवाएं बहाल कर रहे हैं। हम सबसे पहले आवश्यक वस्तुओं के मौजूदा ऑर्डरों की डिलिवरी कर रहे हैं और केवल इन उत्पादों के ही ऑर्डर स्वीकार कर रहे हैं।' यह अग्रणी कंपनी अब तक आवश्यक वस्तुओं के लिए अपनी सेवाएं बेंगलूरु, पुणे, लुधियाना, लखनऊ, मैसूर, नोएडा, रायपुर, कोलकाता और हैदराबाद में बहाल कर चुकी है। ई-हेल्थ स्टार्टअप मेडलाइफ करीब 20 शहरों में फिर से अपनी सेवाएं चालू कर चुकी है। कंपनी अपनी आपूर्ति शृंखला को प्रबंधित करने के तरीके तलाश रही है। कंपनी के सह-संस्थापक और सीईओ अनंत नारायण कहते हैं कि इस समय कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती काम के लिए कर्मचारी हासिल करना है। उन्होंने कहा, 'इस समय हमें यह मजबूत संदेश देने की जरूरत है कि हम सभी एहतियात बरत रहे हैं और लोगों को वापस लौटने और आवश्यक सेवाओं के लिए काम करने का भरोसा देते हैं।' कंपनी के प्लेटफॉर्म पर नियमित ऑर्डरों की तुलना में दोगुने या तिगुने ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन उसके पास कर्मचारी करीब 50 फीसदी कम हो गए हैं।

ऑनलाइन किराना स्टोर बिगबास्केट फिर से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह पिछले एक सप्ताह से अपने ऐप पर बीबी स्टार ग्राहकों के भी ऑर्डर नहीं ले रहा है। सुपर डेली जैसी स्टार्टअप अब केवल दूध की आपूर्ति कर रही हैं और सब्जी, अंडे और ब्रेड जैसे अन्य उत्पादों की डिलिवरी बंद कर दी है। ब्रांडेड मीट और पोल्ट्री डिलिवरी स्टार्टअप लिसियस भी एक सप्ताह से अधिक समय से चल नहीं रही है। इसके ऐप पर सभी चीजें खत्म हैं।